साप्ताहिक
शहर सत्ता
RNI TITLE CODE - CHHHIN17596
सोमवार, 11 अगस्त से 17 अगस्त 2025
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 10 में...
बीजेपी का घर घर तिरंगा पाखंड: कांग्रेस

पेज 04 में...
प्रदेश में रणनीतिक खनिजों का भंडार

वर्ष : 01 अंक : 23 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com
पेज 07 वनडे से भी संन्यास लेंगे रोहित-कोहली

'गौ'... ठान से धाम तक !

छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान से जरा हटकर गौधाम योजना

- गोबर खरीदी नहीं होगी, लेकिन चारा विकास को बढ़ावा मिलेगा
- एक एकड़ के लिए 47,000 तो 5 एकड़ के लिए 2,85,000 रुपये
- चरवाहों को 10,916 और गौसेवकों को 13,126 रु मासिक मानदेय
- हर गौधाम में अधिकतम 200 पशु रखे जाने की क्षमता होगी तय

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

पूर्ववर्ती कांग्रेस शासक भूपेश बघेल से लेकर उन्हें सत्ताच्युत करके आई विष्णुदेव सरकार एक बार फिर 'गौ' सेवा के लिए नए कलेवर, नए तेवर के साथ गौठान से निकालकर गायों को गौधाम पहुंचाने प्रतिबद्ध है। फ़िलहाल गौठान से ज्यादा छत्तीसगढ़ की गायों को सड़कें ज्यादा पसंद हैं। लेकिन बिलासपुर हाई कोर्ट की फटकार के बाद और पूरवर्ती कांग्रेस सरकार की 'ठान' से जरा हटकर 'गौ' सेवा के लिए सुशासन सरकार 'धाम' योजना ले आई है। इसके तहत गोबर खरीदी नहीं होगी, लेकिन चारा विकास को बढ़ावा मिलेगा—एक एकड़ के लिए 47,000 रुपये और पांच एकड़ के लिए 2,85,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना में अवैध तस्करी और घुमंतु पशुओं की सुरक्षा पर विशेष जोर होगा। हर गौधाम में अधिकतम 200 पशु रखे जा सकेंगे। चरवाहों को 10,916 रुपये और गौसेवकों को 13,126 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। चारे के लिए प्रतिदिन निर्धारित राशि दी जाएगी और उत्कृष्ट गौधाम को पशुओं की संख्या के आधार पर पहले वर्ष 10 रुपये से चौथे वर्ष तक 35 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन सहायता मिलेगी।

गौधाम योजना के यह लाभ

- पशुधन की सुरक्षा
- नस्ल सुधार
- जैविक खेती,
- चारा विकास
- गौ-आधारित उद्योगों को बढ़ावा
- निराश्रित गौवंशीय पशुओं की देखभाल
- चरवाहों-गौसेवकों को नियमित आय लाभ

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए 'गौधाम योजना' शुरू कर रही है। यह योजना पशुधन की सुरक्षा, नस्ल सुधार, जैविक खेती, चारा विकास और गौ-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी। इसके तहत निराश्रित और घुमंतु गौवंशीय पशुओं की देखभाल के साथ चरवाहों व गौसेवकों को नियमित आय का साधन मिलेगा। गौधाम चयन के लिए सुरक्षित शासकीय भूमि, पानी, बिजली और शेड की सुविधा जरूरी होगी। संचालन में पंजीकृत गौशालाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, ट्रस्ट, किसान उत्पादक कंपनियों और सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गौधाम स्थापित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौधाम योजना से पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, नस्ल सुधार को बढ़ावा मिलेगा और ग्राम स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

सुलगते सवाल

1. सियासत में गाय की अचानक एंट्री कैसे हुई
2. क्या अब शासन गौ-कैबिनेट भी बनाएगी
3. कांग्रेस 1000 गौशाला का फॉर्मूला लाई बीजेपी कितने का लाएगी
4. क्या एमपी की तर्ज में गायों के आधार कार्ड सीजी में बनेंगे
5. भाजपा को 2014 में तो कांग्रेस को 2018 को क्यों आई गौसेवा की याद
6. क्यों नहीं कांग्रेस और बीजेपी गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती
6. देशभर में गायों का वध और उत्पाद कारखानों के लिए सख्त नियम क्यों नहीं बनता

साप्ताहिक शहर सत्ता

सियासी गौठान, गौधन, गौसेवा

भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के दौर में शुरू हुई गौठान योजना कभी छत्तीसगढ़ की 'गौ सेवा' की पहचान बताई जाती थी। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी, जैविक खाद निर्माण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का दावा... लेकिन समय के साथ यह योजना घोटालों के आरोपों में घिर गई। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नतीजे जमीन पर नहीं दिखे। बीजेपी ने सत्ता में आते ही इस योजना पर ताला जड़ दिया, यह कहते हुए कि "गौ सेवा के नाम पर कांग्रेस ने सरकारी खजाने को चट कर दिया।"

भूपेश के समय गायों को यह बजट

भूपेश बघेल का गौठान बजट: लगभग ₹175 करोड़ (सालाना आवंटन, गोबर खरीदी व संचालन के लिए)

क्या पुराना क्या नया?

- गोबर खरीदी नहीं होगी, अब फोकस चारा विकास पर।
- 1 एकड़ चारा उत्पादन के लिए ₹47,000, 5 एकड़ के लिए ₹2,85,000 की सहायता।
- हर गौधाम में अधिकतम 200 पशु रखने की सीमा तय।
- चरवाहों को ₹10,916/माह, गौसेवकों को ₹13,126/माह मानदेय।
- उत्कृष्ट गौधाम को पहले साल ₹10, दूसरे साल ₹20, तीसरे साल ₹30 और चौथे साल ₹35 प्रति पशु प्रतिदिन अतिरिक्त सहायता।
- अवैध तस्करी और घुमंतु पशुओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान।

गौसेवा पॉलिटिक्स, किस्सा यहीं खत्म नहीं होगा

सत्ता परिवर्तन के बाद भी गायों की हालत नहीं सुधरी। सड़कों पर भटकती, भूखी-प्यासे दम तोड़ती गायों की तस्वीरें और बिलासपुर हाईकोर्ट की फटकार ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। नतीजा—भूपेश बघेल के 'गौठान' को बंद करने वाली विष्णुदेव साय सरकार अब लगभग उसी ढांचे को नए नाम और नए तेवर में पेश करने जा रही है—'गौधाम योजना'।

यूपी की योजना से मेल, ली प्रेरणा

इस 'गौधाम योजना' के कई प्रावधान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की गौ सेवा योजनाओं से मेल खाते हैं। यूपी में भी गौशालाओं के लिए स्थायी अनुदान, चारा विकास और गौ-आधारित उत्पादों पर जोर है। फर्क इतना कि यूपी में गोबर आधारित उत्पाद निर्माण को बढ़ावा है, जबकि छत्तीसगढ़ में इस बार गोबर खरीदी पूरी तरह बंद रहेगी।

साय सुशासन का यह गौधाम मॉडल

फिलहाल आधिकारिक कुल बजट का खुलासा नहीं, लेकिन चरवाहा-गौसेवक मानदेय, चारा अनुदान और संरचना निर्माण को मिलाकर सैकड़ों करोड़ की योजना होने का अनुमान।

1.90 करोड़ खर्च, 1300 करोड़ के घोटाले की गूंज

छत्तीसगढ़ में गायों के पीछे सरकारें करोड़ों खर्चती रहीं। लेकिन गौधन, गौसेवा, नस्ल और सड़क हादसे में कोई करिश्मा नहीं दिखा। एक बार फिर चमत्कारी उम्मीदों को लेकर अब गौधाम योजना फ्लोर पर है। बताते हैं पूर्व में गौठानो में 1 हजार 90 करोड़ खर्चा हुआ और सदन में 1300 करोड़ के घोटाले की गूंज अभी थमी नहीं है। फ़िलहाल गौधाम योजना के इम्प्लीमेंट के लिए सुशासन सरकार कितना खरचेगी इसके पुख्ता आंकड़े नहीं मालूम।

योजना पर कांग्रेसी तोहमत

गौ माता को अपमानित करने "गौधाम" षड़यंत्र

गौधाम योजना पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार का गौधाम योजना गौ माता को अपमानित करने वाला है। भाजपा सरकार की गौ विरोधी होने का प्रमाण है। गौधाम योजना तो बना दिया गया। लेकिन गौधाम निर्माण के लिए कोई राशि स्वीकृत नही की गई। गौधाम बनाने में निर्माण में होने वाला खर्च कहाँ से आयेगा? क्या गोठनों को ही नाम बदलकर गौ धाम बनाया जायेगा? गौधाम योजना के तहत पशुधन के लिए प्रति पशुधन प्रतिदिन 10 रु चारा के लिए तय किया गया है। सरकार बताये 10 रु में पशुधन को भरपेट आहार कैसे मिलेगा? 10 रु में कौन सा पशुआहार मिलता है? बाजार में पशुआहार खल्ली चुन्नी भूसी की कीमत 40 रु से 50 रु किलो से ऊपर है। एक दिन में एक पशुधन को 12 किलो से अधिक आहार खुराक के लिए आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में 10 रु की चारा में पशुधन का संरक्षण एवं नस्ल सुधार कैसे होगा?

गौठान अब गौधाम भाजपा सरकार का यू -टर्न

पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा आरंभ किए गए गौठान योजना का नाम बदलकर गौधाम के नाम से संचालित करने के निर्णय को भाजपा सरकार का यू -टर्न करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार अंततः गौठानो का नाम बदलकर शुरू करने मजबूर हुई। जो लोग राजनैतिक दुर्भावनावश गोठान का विरोध कर रहे थे, विगत 20 महीनों में स्वयं की कोई योजना ला नहीं सके, अब गौ वंशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए वापस उन्हें गोठानो का आश्रय लेना पड़ रहा है। चुनाव के समय जो गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं, वही भाजपाई उन्हें अब आवारा पशु कह रहे हैं। भाजपा सरकार की अकर्मण्यता और दुर्भावनापूर्ण निर्णय से 10 हजार से अधिक गौठानो में ताले लगे और किसके चलते सैकड़ो की संख्या में गाय सड़क पर कुचलकर मार दी गई उस पाप के लिए यह सरकार ही जिम्मेदार है।

एनएसजी गुड़गांव की टीम ने पीएसओ एवं पुलिस वाहन चालकों को दिया प्रशिक्षण

रायपुर। वर्तमान समय में व्हीआईपी सुरक्षा, पुलिस की महत्वपूर्ण ड्यूटी मे से एक है, उक्त ड्यूटी में कार्यरत जवानो को समय-समय पर अपने कौशल एवं व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि करना आवश्यक होता है, इसी उद्देश्य की पूर्ती हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, श्री अमित कुमार, भारतीय पुलिस सेवा के प्रयास एवं मार्गदर्शन में व्हीआईपी सुरक्षा में लगे अधिकारी-कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एन.एस.जी. मानेसर (गुड़गांव) की 13 सदस्यीय दल विगत 14 जुलाई 2025 से रायपुर में रहकर प्रशिक्षण दे रही है। व्हीआईपी सुरक्षा में कार्यरत जवानों के साथ-साथ पुलिस के वाहन चालकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान सुरक्षा के मद्देनजर होता है, इसलिए जवानो के साथ-साथ पुलिस के वाहन चालकों को भी 06 दिवसीय टैक्टीकल ड्रायविंग प्रशिक्षण एनएसजी द्वारा दिया जा रहा है।

इस प्रयोजन हेतु प्रथम बैच में दिनांक 14.07.2025 से 26.07.2025 तक 79 एवं द्वितीय बैच दिनांक 28.07.2025 से 08.08.2025 तक 112 कुल 197 पीएसओ एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के 44 वाहन चालकों को 06 दिवसीय, आपातकालिन स्थिति में किये जाने ड्रील एवं व्हीआईपी सुरक्षा में किये जाने वाले कार्यो का प्रशिक्षण दिया गया।

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्हीआईपी सुरक्षा वाहिनी माना में पीएसओ एवं पुलिस वाहन चालकों का संयुक्त अभ्यास एनएसजी के नेतृत्व में कराया गया। जिसमें आपातकालीन परिस्थिति में वाहन चालकों एवं पीएसओ द्वारा क्या किया जाना है विस्तार से डेमो एवं ड्रिल के द्वारा समझाया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता श्री अमित कुमार, भा.पु.से., द्वारा डेमो ड्रील का मुवायना किया गया। विदित हो कि वर्ष 2023 से लगतार एनएसजी का प्रशिक्षण दस्ता रायपुर आकर छत्तीसगढ़ पुलिस के वाहन चालकों एवं व्हीआईपी सुरक्षा मे कार्यरत कर्मियों को प्रशिक्षित करने का कार्य रही है।

एनएसजी ग्रुप कमांडर अशोक कुमार पी. ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुलिस जवानों की सराहना किया तथा पुलिस जवान के धैर्य तथा समर्पण की भावना से प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कही। सेनानी व्हीआईपी सुरक्षा वाहिनी ने सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या आदि के बारे में बताया तथा पुलिस में प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया साथ ही एनएसजी प्रशिक्षण टीम के द्वारा दी जा रही प्रशिक्षण की सराहना की एवं बताया कि सुरक्षा में कार्यरत जवानो को रायपुर में बेसिक पीएसओ कोर्स के अलावा उच्च प्रशिक्षण हेतु CRPF ट्रेनिंग सेन्टर ग्रेटर नोएडा, मोईनाबाद तेलंगाना पुलिस, NSG ट्रेनिंग सेन्टर मानेसर भी भेजा जाता रहा है।

सरेआम खेल रहे थे जुआं, पुलिस ने किया गिरफ्तार

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर पुलिस की एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की कार्यवाही में थाना गंज क्षेत्रांतर्गत होटल महिन्द्रा के पास स्थित गली में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 06 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। जुआ खेलते आधा दर्जन जुआरियों के कब्जे से नगदी रकम 31,270/- रूपये जप्त किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी

- योगेश अग्रवाल पिता प्रदीप अग्रवाल उम्र 48 वर्ष निवासी राम नगर दिशा कालेज के पास, रायपुर।
- योगेश साहू पिता एन एल साहू उम्र 45 वर्ष निवासी खम्हारडीह विधानसभा रोड, रायपुर।
- परमानंद चमेडिया पिता स्व. मखमल चमेदिया उम्र 64 वर्ष निवासी बेगम पडे थाना बेगम पडे जिला हैदराबाद तेलंगाना।
- सतीश अग्रवाल पिता ओम प्रकाश अग्रवाल उम्र 55 वर्ष निवासी समता कालोनी रायपुर।
- गोपाल महेश्वरी पिता कैलाश महेश्वरी उम्र 41 वर्ष निवासी आमासिवनी रायपुर।
- सुनील अग्रवाल पिता एस एल अग्रवाल उम्र 53 वर्ष निवासी गोल चौक डी.डी. नगर रायपुर।

नवा रायपुर में अवैध मुरुम उत्खनन पुलिस और एनआरडीए की कार्रवाई

शहर सत्ता/रायपुर। खनन माफियाओं एवं अवैध रूप से उत्खनन करने वालो के विरूद्ध रायपुर पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही की है। थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत अवैध रूप से मुरूम उत्खनन एवं परिवहन कर चोरी एवं चोरी का प्रयास करने वाले जे.सी.बी., हाईवा एवं ट्रैक्टर वाहन चालकों के मालिकों पर चोरी की धारा के तहत एफआईआर पंजीबद्ध किया गया। मामला NRDA के आवेदन के आधार पर FIR किया है। सूचना प्राप्त हुई की थाना मंदिर हसौद ग्राम नवागांव छतौना अटल नगर रेलवे स्टेशन के पास रोड नं. 06 NRANVP की शासकीय भूमि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जे.सी.बी. एवं हाईवा वाहन में अवैध रूप से मुरूम खनन एवं परिवहन कर चोरी एवं चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अटल नगर नवा रायपुर एवं थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद एवं एन.आर.डी.ए. की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान जे.सी.बी. वाहन से अवैध रूप से मुरूम खनने करते जे.सी.बी., हाईवा एवं ट्रैक्टर वाहन को पकड़ा गया। सभी से मुरूम खनन एवं परिवहन करने के संबंध में शासन का वैध कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से मुरूम खनन एवं परिवहन कर चोरी एवं चोरी करने का प्रयास करने में प्रयुक्त जे.सी.बी, हाईवा एवं ट्रैक्टर वाहन जप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए आज उनके विरूद्ध NRDA के आवेदन पर थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 345/25 धारा 303, 62 बी.एन.एस., खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा 4/21 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

चार दिनों में धरदबोचे गए 50 ड्रंकन ड्राइव के आरोपी

10-10 हजार रूपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया

शहर सत्ता/रायपुर। देर रात ड्रंकन ड्राइव करने वाले चालकों के विरूद्ध रायपुर पुलिस की विषेष अभियान कार्यवाही में सख्ती दिखी। रात्रि 11 बजे से 2 बजे तक शहर में अलग-अलग पाइंटो पर बेरिकेटिंग कर चेकिंग अभियान चलाया गया। राजधानी पुलिस का पूरा अमला पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा के निर्देशन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के मार्गदर्शन में 22 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर प्रकरण निराकरण हेतु कोर्ट भेजा।

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देष पर यातायात पुलिस रायपुर द्वारा नशेड़ी वाहन चालकों के विरूद्ध सख्त रूख अपनाते हुए विषेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत शहर के प्रमुख मार्गो एवं प्रमुख चौंक-चौराहों में यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बेरिकेटिंग कर नशे की हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की ब्रीथ नालाईजर मषीन द्वारा चेकिंग कार्यवाही की जा रही है। नषे की हालत में वाहन चलाते पाये जाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण कोर्ट भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

न्यायालय द्वारा 10-10 हजार रूपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। साथ ही वाहन चालक का लायसेंस तीन माह के लिए सस्पेड किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। यह अभियान प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से 02:00 बजे रात्रि तक चलाया जा रहा है।

क़त्ल के जुर्म में 19 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार

शहर सत्ता/रायपुर। थाना खरोरा पुलिस द्वारा हत्या के मामले 19 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया।

बताते हैं क़त्ल का आरोपी रवेल आडिल पिता गंगूराम आडिल उम्र-70 वर्ष पता ग्राम काकडीह थाना आरंग जिला-रायपुर है। पुलिस के मुताबिक मुखबीर से सूचना मिली थी कि रवेल आडिल पिता गंगूराम आडिल उम्र-70 वर्ष पता ग्राम काकडीह थाना आरंग जिला-रायपुर जो अपने गांव में आने की सूचना पर थाना प्रभारी खरोरा नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर उक्त वारंटी को पकड़ा गया जो घटना दिनांक 02/06/2006 विगत 19 वर्षो से हत्या ,हत्या का प्रयास और बलवा के मामले में फरार था। आरोपी रावेल अप.क्र.153/06 धारा-147,148,149,302,307, 450 भा.द.वि.के तहत स्थायी वारंटी था। जिसको खरोरा पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त स्थायी वारंटी को पकडऩे में थाना खरोरा प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार कुशवाहा, प्र.आर.हिरेन्द्र वर्मा आर.मुकेश चौहान, गजानंद ध्रुवंशी, सुरेन्द्र चौहान का सराहनीय योगदान रहा है।

रक्षाबंधन पर रायपुर पुलिस की सौगात

ऑपरेशन मुस्कान से 581 गुमशुदा बच्चों को परिजनों को सौंपा

शहर सत्ता/रायपुर। रक्षाबंधन पर्व से ठीक पहले रायपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान एवं अभियान तलाश के तहत 581 गुमशुदा बच्चों को उनके परिजनों से मिलाकर इस पर्व को सच्चे अर्थों में सार्थक बना दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे इस मानवीय अभियान ने न केवल बच्चों को उनके परिवार से जोड़ा, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते को एक नई गरिमा भी प्रदान की।

इस अभियान के माध्यम से जिन बहनों को वर्षों से अपने गुमशुदा भाई की प्रतीक्षा थी, उन्हें न केवल उनका भाई मिला, बल्कि कई बहनों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर पुलिस जवानों के रूप में नए भाई भी मिल गए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को राखी बांधकर स्नेह और कृतज्ञता प्रकट की। रायपुर पुलिस द्वारा पिछले दो माह में प्रोजेक्ट मुस्कान एवं अभियान तलाश के तहत 581 बच्चों को खोजकर उनके परिजनों से मिलाया गया है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में दो बहनों ने अपने लापता भाइयों के सकुशल मिलने पर थाना प्रभारी को राखी बांधकर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह रक्षाबंधन उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि रायपुर पुलिस ने उन्हें उनका खोया हुआ भाई वापस दिलाया। गुढ़ियारी थाना प्रभारी श्री बी.एल. चंद्राकर ने बताया कि जैसे ही किसी बालक या बालिका की गुमशुदगी की सूचना प्राप्त होती है, तुरंत प्रोजेक्ट मुस्कान के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। आवश्यक जाँच के उपरांत बच्चे को खोजकर सुरक्षित रूप से परिजनों को सौंपा जाता है।

रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र के राम केशरवानी 23 जुलाई को घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। पुलिस ने तत्परता से मामला दर्ज कर उन्हें खोजकर परिजनों से मिलाया। उनकी बहन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस अधिकारी को राखी बांधी।

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 59 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

शहर सत्ता/रायपुर। रेंज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय रायपुर की त्वरित कार्रवाई में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले आरोपी को 24 परगना, पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से जप्त बैंक खातों में अलग अलग राज्यों के कुल 66 से अधिक पुलिस थानों/साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज है। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी विकास लाहोटी पिता मोतीलाल लाहोटी पता जयश्री विहार पंडरी रायपुर ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम से उनसे 59 लाख रुपए की धोखाधड़ी होने की रिपोर्ट रेंज साइबर थाना रायपुर में पंजीबद्ध कराई थी, रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 04/24 धारा 420,34 भादवि दिनांक 24/6/24 को पंजीबद्ध किया गया था। गिरफ्तार आरोपी प्रताप पात्रा पिता धनंजय पात्रा उम्र 33 वर्ष स्थायी पता 29/03 प्रोसांता राय रोड पूर्वा बरीसा, थाना हरिदेवपुर साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल वर्तमान पता 69 टी/8 बख्तीयार रोड नवीना सिनेमा हाल कोलकाता वेस्ट बंगाल है। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा द्वारा रेंज साइबर थाना रायपुर की टीम को तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के संबंध में निर्देश दिया गया था।

साप्ताहिक शहर सत्ता

महासमुंद में निकेल, क्रोमियम और पीजीई की खोज

छत्तीसगढ़ बना रणनीतिक खनिजों का नया हब

खनिज विकास के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा— "यह खोज आत्मनिर्भर भारत की दिशा में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान है। हम वैज्ञानिक और सुनियोजित खनिज विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"

रायपुर। छत्तीसगढ़ ने खनिज संपदा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। महासमुंद जिले के भालुकोना–जामनीडीह ब्लॉक में निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स (PGE) की मौजूदगी की पुष्टि के साथ, राज्य अब रणनीतिक और क्रिटिकल मिनरल्स के राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रमुख स्थान हासिल करने की ओर बढ़ रहा है।

रणनीतिक महत्व क्यों?

निकेल, क्रोमियम और पीजीई जैसे खनिज सिर्फ स्टील या औद्योगिक धातुओं के लिए नहीं, बल्कि बैटरी निर्माण, हरित ऊर्जा, एयरोस्पेस, डिफेंस और हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी खपत वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रही है और चीन, दक्षिण अफ्रीका व रूस जैसे देशों का इन पर पारंपरिक दबदबा रहा है। ऐसे में भारत में इनकी खोज को आयात निर्भरता घटाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है।

कैसे मिली यह सफलता?

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने पहले इस क्षेत्र में संभावना जताई थी। राज्य के खनिज संसाधन विभाग ने ई-नीलामी के जरिए 6 मार्च 2023 को इस ब्लॉक का आवंटन किया। मेसर्स डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड (DGML) ने 21% की उच्चतम बोली लगाकर इसे हासिल किया। ड्रोन सर्वे, रॉक सैंपलिंग और भूभौतिकीय अध्ययन से 700 मीटर लंबी और 300 मीटर गहराई तक सल्फाइड खनिज पट्टी के संकेत मिले। भालुकोना–जामनीडीह के अलावा, पास के केलवरडबरी ब्लॉक का विकास वेदांता लिमिटेड कर रही है। इन दोनों क्षेत्रों का संयुक्त दोहन महासमुंद को भारत के रणनीतिक खनिज क्लस्टर के रूप में स्थापित कर सकता है।

राज्य में अब तक की प्रगति

- छत्तीसगढ़ में अब तक 51 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है।
- इनमें निकेल, क्रोमियम, PGE, लिथियम, ग्रेफाइट, फास्फोराइट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स शामिल हैं।
- छह टिन ब्लॉक्स केंद्र सरकार को नीलामी के लिए सौंपे गए हैं।
- खनिज खोज और परिशोधन को गति देने के लिए राज्य सरकार ने क्रिटिकल मिनरल सेल का गठन किया है।

रायपुर के सरकारी दफ्तरों में 90% से अधिक शिकायतें लंबित

रायपुर। राजधानी के सरकारी कार्यालयों में जनता की शिकायतें और आवेदन तो दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन उनका समाधान महीनों तक नहीं हो रहा। जनवरी से अगस्त 2025 तक रायपुर जिले के विभिन्न विभागों में कुल 52,413 शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 47,518 मामले अब तक लंबित हैं। यानी 90 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

जमीन संबंधी मामलों में सबसे ज्यादा लापरवाही

आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक लंबित मामले रायपुर तहसील कार्यालय में हैं, जहां 10,807 प्रकरण कई महीनों से अटके पड़े हैं। इनमें अधिकांश जमीन से जुड़े विवाद हैं, जैसे नामांतरण, बटांकन, मुआवजा और कब्जा दिलाने के आवेदन। आरंग तहसील 6,000 से अधिक लंबित मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। नगर निगम रायपुर की स्थिति भी बेहतर नहीं है। यहां पिछले आठ महीनों में 6,408 शिकायतें और आवेदन आए, जिनमें से 6,047 पर अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। यही हाल बिरगांव नगर निगम, तिल्दा तहसील, मंदिरहसौद तहसील और नगर निगम के जोन कार्यालयों का है, जहां बड़ी संख्या में आवेदन बिना निपटारे के पड़े हैं।

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड: 200 करोड़ की संपत्ति, आय सिर्फ 5 लाख

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पास करीब 5,000 पंजीकृत संपत्तियां हैं, जिनसे बाजार दर पर सालाना 200 करोड़ रुपये तक किराया आ सकता है, लेकिन मौजूदा हालात यह है कि बोर्ड की कुल वसूली सिर्फ 5 लाख रुपये ही है। कारण इसलिए कि दशकों पुराने किराया अनुबंध, न्यूनतम दरें और संपत्ति पर सीमित परिवारों का कब्जा।

1980 से नहीं बढ़ा किराया

राजधानी रायपुर के बैजनाथ पारा में बोर्ड की एक दुकान का किराया 80 पैसे है, यानी इससे ज्यादा रकम तो रसीद काटने में खर्च हो जाती है। यह दर 1980 में तय हुई थी, इससे पहले यह 35 पैसे थी। बोर्ड की 700 दुकानें 100 से 500 रुपये महीने तक के किराए पर हैं, जबकि बाजार दर 200 वर्गफीट की दुकान का किराया 25,000 से 35,000 है। किराया संशोधन के लिए बोर्ड ने दो बार नोटिस जारी किए, लेकिन दुकानदारों की प्रतिक्रिया शून्य रही। तीसरा नोटिस भेजने की तैयारी है, जिसके बाद भी

भुगतान नहीं हुआ तो सीलिंग की कार्रवाई होगी। बिलासपुर में किराया संशोधन का असर दिखा और 70 दुकानों से आय ₹23,000 से बढ़कर ₹5 लाख सालाना हो गई।

संपत्ति पर कब्जे और दुरुपयोग

कई दुकानें मौलाना, मौलवी और मुतवल्ली परिवारों के कब्जे में हैं। कम किराए पर ली गई दुकानें आगे किराए पर देकर निजी मुनाफा कमाया जा रहा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड का सामाजिक सेवा मिशन अधूरा रह जाता है।

महादेव एप केस में सीबीआई का शिकंजा

150 से अधिक अफसर और नेता राडार पर

रायपुर। महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप घोटाले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले से जुड़े 150 से अधिक पुलिसकर्मियों, आईपीएस और प्रशासनिक अधिकारियों, तथा राजनीतिक नेताओं को समन जारी किया है। सभी को एक सप्ताह के भीतर पूछताछ के लिए हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसी की इस सक्रियता से संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही कई बड़े नामों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

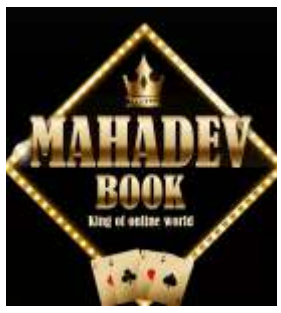

हवाला लेन-देन और चुनावी फंडिंग पर फोकस

सूत्रों के मुताबिक, बीते दो दिनों में सीबीआई ने दो वरिष्ठ अधिकारियों से करीब चार घंटे तक पूछताछ की है। सवाल मुख्यतः प्रोटेक्शन मनी, हवाला ट्रांजेक्शन और राजनीतिक फंडिंग से जुड़े रहे। एक आईपीएस अधिकारी से पूछताछ के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मांगे गए हैं। जांच में सामने आया है कि सट्टेबाजी से निकला काला धन हवाला नेटवर्क के जरिए ऊपर तक पहुंचाया गया, और 2023 के विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक दल को बड़े पैमाने पर फंडिंग के आरोप भी जुड़े हैं।

राजनीति और प्रशासन में बढ़ी हलचल

सीबीआई की ताजा कार्रवाई से राजनीतिक और अफसरशाही गलियारों में हड़कंप है। एजेंसी का फोकस अब उन कड़ियों को जोड़ने पर है जो बेटिंग नेटवर्क से चुनावी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग तक जाती हैं। आने वाले दिनों में और बड़े नामों के उजागर होने की संभावना है।

पुलिस अफसरों के यहां छापे

जांच एजेंसी ने इससे पहले आईपीएस आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल समेत अन्य अधिकारियों के आवास पर छापेमारी की थी। इन पर सट्टेबाजी नेटवर्क से आर्थिक लाभ लेने के आरोप हैं।

नक्सल प्रभावित जंगलों से इंटरनेशनल पावरलिफ्टिंग चैंपियन तक का खुशबू नाग का सफर

अबूझमाड़ की बाहुबली बेटी

नारायणपुर। नक्सलवाद, बम और बारूद की खबरों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाला बस्तर अब अपनी बेटियों की प्रतिभा और उपलब्धियों के लिए पहचाना जाने लगा है। इस बदलाव की चमकदार मिसाल हैं नारायणपुर जिले की आदिवासी बेटी खुशबू नाग, जिन्होंने पुरुष प्रधान समझे जाने वाले बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया।

खुशबू नाग एक साधारण आदिवासी परिवार से आती हैं। उनके पिता पेशे से बढ़ई (कारपेंटर) हैं। साल 2019 में कैंसर से अपनी मां को खोने का दर्द उन्हें गहराई से तोड़ गया। मां की लंबी बीमारी और फिर असमय मृत्यु ने खुशबू को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। इसी दौरान उनके भाई ने उन्हें फिटनेस के लिए जिम जाने की सलाह दी। जिम सिर्फ शरीर को मजबूत करने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि वह खुशबू के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहीं से 2019 के बाद उनका सफर फिटनेस से लेकर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग और पावरलिफ्टिंग की ओर मुड़ गया।

समाज की पुरानी सोच से टक्कर

खुशबू नाग बताती हैं कि इस खेल में करियर बनाने की शुरुआत आसान नहीं थी। नारायणपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में न तो पर्याप्त जिम उपकरण थे, न डाइट सपोर्ट और न ही योग्य कोच। ऊपर से समाज की मानसिकता एक बड़ी चुनौती थी—लोग इसे महिलाओं के लिए उपयुक्त खेल नहीं मानते थे। उन्होंने बताया, "लोगों की सोच को बदलने में समय लगा। शुरुआत में ताने और सवाल झेलने पड़े, लेकिन मैंने हार नहीं मानी।"

नेशनल और इंटरनेशनल उपलब्धियां

खुशबू ने अब तक राष्ट्रीय स्तर की तीन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर तीनों में गोल्ड मेडल जीते। उन्हें "स्ट्रांग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़" का खिताब भी मिला। हाल ही में मुंबई में आयोजित NPC वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकाया। इसके साथ ही उन्हें "स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया" का खिताब भी मिला। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली युवती हैं।

बदल रही है सोच, बढ़ रहा है हौसला

खुशबू का मानना है कि उनकी सफलता ने न सिर्फ नारायणपुर बल्कि पूरे बस्तर की लड़कियों को प्रेरित किया है। "जब मैंने शुरुआत की, तब गिनी-चुनी लड़कियां ही जिम जाती थीं। आज कई लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं। यह बदलाव देखकर गर्व होता है," उन्होंने कहा। खुशबू नाग की कहानी साबित करती है कि संसाधनों की कमी, सामाजिक बंदिशें और कठिन परिस्थितियां भी मजबूत इरादों के सामने टिक नहीं सकतीं। उनकी यह उपलब्धि बस्तर की उन बेटियों के लिए नई राह खोल रही है, जो खेल के माध्यम से अपनी पहचान बनाना चाहती हैं।

संपादकीय

सुकांत राजपूत

बदलती प्रकृति, और प्रवृति

हम सभी को सावचेत रहने की आवश्यकता है। धरातल में सिर्फ बदलती प्रकृति, पर्यावरण ही खतरा नहीं है, बलकि इंसानी प्रवृत्तियां भी जानलेवा हो गई हैं। सावधान रहें, क्योंकि जितनी विविधता प्रकृति की, उतनी ही विविधता इंसान के मिजाज की भी हैं। छत्तीसगढ़ के ही सरगुजा में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक दृष्टिहीन नाबालिग लडक़ी से बार-बार बलात्कार करने वाले उसके सौतेले पिता, और रिश्ते के नाना को आखिरी सांस तक उम्रकैद सुनाई है। दो बरस तक सौतेला पिता इस नेत्रहीन नाबालिग लडक़ी से बलात्कार करते रहा, और इसकी जानकारी मिलने पर उसके रिश्ते के नाना ने भी यही काम किया। ओडिशा से आए एक बच्चा चोर की है जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक सोए हुए परिवार के घर में घुसकर मां-बाप के बीच से छोटे से बच्चे को उठाकर भाग रहा था, और बच्चे के रोने से वह पकड़ में आया तो पता लगा कि वह उसे ले जाकर ओडिशा में बेचने वाला था। तीन लाख से अधिक में वहां कोई बच्चा खरीदने वाला था। राजधानी रायपुर में ही दो साल के एक बेटे को खड़ी हुई मालवाहक गाड़ी में एक चिट्ठी के साथ छोडक़र उसके पोषणकर्ता चले गए, और उसमें खुद की मजबूरियां लिखी थीं कि लिखने वाले को खुदकुशी करनी है, और इस बच्चे को कोई अपना ले। इन दो घटनाओं को देखें तो हैरानी होती है कि एक तरफ बच्चे की हसरत ऐसी है कि लोग चोरी के बच्चे के लिए लाखों रूपए दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह बच्चे को छोडक़र मां-बाप चले गए। इंसानी मिजाज की इतनी किस्में दुनिया में देखने मिलती हैं जितनी कि कुदरत की पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों की विविधता रहती है। लोगों के भीतर ऐसी हिंसक भावनाएं भरी रहती हैं, और कई लोग सामाजिक दबाव में, कई लोग पारिवारिक रिश्तों की वर्जनाओं में, और कुछ लोग अदालती सजा के डर से भले बने रहने का मुखौटा ओढ़े रहते हैं। लोगों को जब तक ऐसी हिंसा, और ऐसे जुर्म करने का पहला मौका न मिले, बिना खतरे के न मिले, तब तक तो हर कोई सज्जन बने ही रहते हैं। अब लोगों को लग सकता है कि ये लोग इंसान नहीं, हैवान हैं। भला कोई इंसान कैसे ऐसी हरकत कर सकते हैं? चौंकिए मत, यह सब कुछ इंसानी मिजाज का एक हिस्सा ही है।

सुशील भोले

कोंदा-भैरा के गोठ

-तोला सुरता हे जी भैरा.. जब हमन प्रायमरी स्कूल म रहेन त ग ले गणेश पढ़ाए जावत रिहिसे.

-सुरता रइही कइसे नहीं जी कोंदा.. बाद म वोला आने धर्म वाले मन के धार्मिक भावना म ठेस पहुँचथे.. ए ह धर्मनिरपेक्ष भावना के अनुरूप नइए कहिके ग ले गमला पढ़ाए गिस.

-ठउका सुरता करे.. फेर अभी रायसेन के एक स्कूल ले क ले काबा, म ले मस्जिद, न ले नमाज अउ औ ले बुर्का वाली औरत पढ़ाए के खबर आए हे.

-करलई हे संगी.. ए तो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के खुल्लमखुल्ला उल्लंघन आय.

-सही कहे.. उहाँ के कुछ हिन्दू संगठन मनला जब ए बात के खबर लगिस त वो मन पुलिस म शिकायत कर के उनला अपन संग लेके वो स्कूल गइन.. उहाँ देखिन के लइका मनला प्रिंटेड किताब दे गे रिहिसे तेने म अइसन लिखाय रिहिसे.

-मतलब ए सब एक सोचे समझे षडयंत्र के अंतर्गत करे जावत रिहिसे?

-हव.. तभे तो लइका मनला उहाँ जेन किताब बाँटे गे रिहिसे तेने म अइसन छपे रिहिसे.. पुलिस ह वो किताब ल मिडिया ल देखावत कार्रवाई करे के बात कहे हे, अब देखव आगू का होथे?

गुलाम थे तो एक थे, आजादी मिलते ही बंट क्यों गए

प्रो. संजय द्विवेदी

भोपाल में जनसंचार विभाग के आचार्य और अध्यक्ष

भारत गुलाम था तो हमारे नारे थे 'वंदेमातरम्' और 'भारत माता की जय'। आजादी के बहुत सालों बाद नारे गूंजे 'भारत तेरे टुकड़े होंगें'। क्या भारत बदल गया है या उसने आजादी के आंदोलन और उसके मूल्यों से खुद को काट लिया है। आजाद भारत की यह त्रासदी है कि बंटवारे की राजनीति आज भी यहां फल-फूल रही है। आजादी का अमृतकाल मनाते हुए भी हम इस रोग से मुक्त नहीं हो पाए हैं। यह सोचना कितना व्यथित करता है कि जब हम गुलाम थे तो एक थे, आजाद होते ही बंट गए। यह बंटवारा सिर्फ भूगोल का नहीं था, मनों का भी था। इसकी कड़वी यादें आज भी तमाम लोगों के जेहन में ताजा हैं। आजादी का अमृतकाल वह अवसर है कि हम दिलों को जोड़ने, मनों को जोड़ने का काम करें। साथ ही विभाजन करने वाली मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकें और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ें। भारत चौदहवीं सदी के ही पुर्तगाली आक्रमण के बाद से ही लगातार आक्रमणों का शिकार रहा है।

16वीं सदी में डच और फिर फ्रेंच, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी इसे पददलित करते रहे। इस लंबे कालखंड में भारत ने अपने तरीके से इसका प्रतिवाद किया। स्थान-स्थान पर संघर्ष चलते रहे। ये संघर्ष राष्ट्रव्यापी, समाजव्यापी और सर्वव्यापी भी थे। इस समय में आपदाओं, अकाल से भी लोग मरते रहे। गोरों का यह वर्चस्व तोड़ने के लिए हमारे राष्ट्र नायकों ने संकल्प के साथ संघर्ष किया और आजादी दिलाई। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते समय सवाल उठता है कि क्या हमने अपनी लंबी गुलामी से कोई सबक भी सीखा है? आजादी के आंदोलन में हमारे नायकों की भावनाएं क्या थीं? भारत की अवधारणा क्या है?यह जंग हमने किसलिए और किसके विरूद्ध लड़ी थी? क्या यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का अभियान था? इन सवालों का उत्तर देखें तो हमें पता चलता है कि यह लड़ाई स्वराज की थी, सुराज की थी, स्वदेशी की थी, स्वभाषाओं की थी, स्वावलंबन की थी। यहां 'स्व' बहुत ही खास है। समाज जीवन के हर क्षेत्र, वैचारिकता ही हर सोच पर 'अपना विचार' चले। यह भारत के मन की और उसके सोच की स्थापना की लड़ाई भी थी। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, वीर सावरकर हमें उन्हीं जड़ों की याद दिलाते हैं।

आज देश को जोड़नेवाली शक्तियों के सामने एक गहरी चुनौती है, वह है देश को बांटने वाले विचारों से मुक्त कराना। भारत की पहचान अलग-अलग तंग दायरों में बांटकर, समाज को कमजोर करने के कुत्सित इरादों को बेनकाब करना। देश के हर मानविंदु पर सवाल उठाकर, नई पहचानें गढ़कर मूर्तिभंजन का काम किया जा रहा है। नए विमर्शों और नई पहचानों के माध्यम से नए संघर्ष भी खड़े किए जा रहे हैं। खालिस्तान, नगा, मिजो, माओवाद, जनजातीय समाज में अलग-अलग प्रयास, जैसे मूलनिवासी आदि मुद्दे बनाए जा रहे हैं। जेहादी और वामपंथी विचारों के बुद्धिजीवी भी इस अभियान में आगे दिखते हैं। भारतीय जीवन शैली, आयुर्वेद, योग, भारतीय भाषाएं, भारत के मानबिंदु, भारत के गौरव पुरूष, प्रेरणापुंज सब इनके निशाने पर हैं। राष्ट्रीय मुख्यधारा में सभी समाजों, अस्मिताओं का एकत्रीकरण और विकास के बजाए तोड़ने के अभियान तेज हैं। इस षडयंत्र में अब देशविरोधी विचारों की आपसी नेटवर्किंग भी साफ दिखने लगी है। संस्थाओं को कमजोर करना, अनास्था, अविश्वास और अराजकता पैदा करने के प्रयास भी इन गतिविधियों में दिख रहे हैं। 1857 से 1947 तक के लंबे कालखंड में लगातार लड़ते हुए।

आम जन की शक्ति भरोसा करते हुए। हमने यह आजादी पाई है। इस आजादी का मोल इसलिए हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। दुनिया के सामने लेनिन, स्टालिन, माओ के राज के उदाहरण सामने हैं। मानवता का खून बहाने के अलावा इन सबने क्या किया। इनके कर्म आज समूचे विश्व के सामने हैं। यही मानवता विरोधी और लोकतंत्र विरोधी विचार आज भारत को बांटने का स्वप्न देख रहे हैं। आजादी अमृत महोत्सव और गणतंत्र दिवस का संकल्प यही हो कि हम लोगों में भारतभाव, भारतप्रेम, भारतबोध जगाएं। भारत और भारतीयता हमारी सबसे बड़ी और एक मात्र पहचान है, इसे स्वीकार करें। कोई किताब, कोई पंथ इस भारत प्रेम से बड़ा नहीं है। हम भारत के बनें और भारत को बनाएं। भारत को जानें और भारत को मानें। इसी संकल्प में हमारी मुक्ति है। हमारे सवालों के समाधान हैं। छोटी-छोटी अस्मिताओं और भावनाओं के नाम पर लड़ते हुए हम कभी एक महान देश नहीं बन सकते। समाज को तोड़ने उसकी सामूहिकता को खत्म करने के प्रयासों से अलग हटकर हमें अपने देश को जोड़ने के सूत्रों पर काम करना है। जुड़कर ही हम एक और मजबूत रह सकते हैं। समाज में देश तोड़ने वालों की एकता साफ दिखती है, बंटवारा चाहने वाले अपने काम पर लगे हैं। इसलिए हमें ज्यादा काम करना होगा। पूरी सकारात्मकता के साथ, सबको साथ लेते हुए, सबकी भावनाओं का मान रखते हुए। यह बताने वाले बहुत हैं कि हम अलग क्यों हैं। हमें यह बताने वाले लोग चाहिए कि हम एक क्यों हैं, हमें एक क्यों रहना चाहिए।

इसके लिए वासुदेव शरण अग्रवाल, धर्मपाल, रामधारी सिंह दिनकर,मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, विद्यानिवास मिश्र, निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा जैसे अनेक लेखक हमें रास्ता दिखा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस को हम अपने संकल्पों का दिन बनाएं, एक भारत-श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ें तो यही बात भारत मां के माथे पर सौभाग्य का तिलक बन जाएगी। हमारी आजादी के आंदोलन के महानायकों के स्वप्न पूरे होंगें, इसमें संदेह नहीं। 9 अगस्त को क्रांति दिवस भी है और 15 अगस्त को आजादी का दिन हम मिलकर मनाएंगें। इस संयुक्त प्रसंग पर हमारा एक ही मंत्र हो सकता है- भारत को जानो, भारत को मानो। भारत के बने, भारत को बनाओ।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

बुजुर्गों की 'रक्षा' भी रक्षाबंधन का ही रूप

एन. रघुरामन

रक्षाबंधन के दौरान अकसर बहनें उनको मिलने वाले नेग या गिफ्ट के लिए भाइयों पर खेल-खेल में तंज कसती हैं या हास्यपूर्ण 'झगड़ा' करती हैं। यह लगाव जताने या मजाक का हल्का-फुल्का तरीका है। चूंकि यह मजाक वाली 'लड़ाई' पूरी तरह से संख्याओं (नेग की राशि) को लेकर है तो आज मैं कॉलम की शुरुआत कुछ विचारणीय संख्याओं के साथ करता हूं। भारत में बुजुर्ग आबादी महत्वपूर्ण तरीके से और तेजी से बढ़ रही है। 2021 में लगभग 13.8 करोड़ बुजुर्ग थे। अगले साल, 2026 में यह संख्या 17.3 करोड़ और पांच साल बाद 2031 में 19.3 करोड़ हो जाएगी। 2050 तक इसके 34.7 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

यह जनसांख्यिकीय बदलाव भारत के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सेवा तंत्र के लिए अवसर और चुनौतियां, दोनों ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होने जा रही है, वो यह है कि संयुक्त परिवारों से एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हमारे पारिवारिक ढांचे में ये बुजुर्ग अकेले और बेसहारा हो सकते हैं। रीयल एस्टेट में काम करने वालों को इन संख्याओं में अवसर दिख रहा है। रीयल एस्टेट सेवा कंपनी 'सेविल्स इंडिया' ने सर्वे में पाया कि तेजी से उम्रदराज हो रही इस आबादी को विशेष रूप से निर्मित घरों की जरूरत है। यदि 2031 तक के 17.3 करोड़ बुजुर्गों को ही लें तो सर्वे कहता है कि 2025 और 2030 के बीच लगभग 72 हजार करोड़ के निवेश की जरूरत होगी। यदि वे अलग-थलग पड़ जाते हैं तो चाहेंगे कि कम्युनिटी में रहें। यही कारण है कि रीयल एस्टेट वाले वरिष्ठजनों के रहने लायक एक बुनियादी ढांचे को आकार देने में व्यस्त हैं। डेवलपर्स ने इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेना शुरू कर दिया है। यह बड़े शहरों में नहीं, बल्कि वडोदरा, कोयंबटूर और गोवा जैसी छोटी जगहों पर दिखाई दे रहा है, जहां निर्माणाधीन परियोजनाओं में से लगभग 34% इसी श्रेणी के लिए हैं। देश में बुजुर्गों की आबादी की, कुल आबादी से तुलना करके इस मुद्दे को खारिज ना करें। हालांकि, भारत की बुजुर्ग आबादी स्वतंत्र रूप से बढ़ रही है। लेकिन अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें तो कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी बेहद कम लगती है। 2024 में जापान दुनियाभर में उम्रदराज आबादी के मामले में अग्रणी था।

वहां कुल आबादी में करीब 36% वरिष्ठ नागरिक थे। लेकिन वैश्विक जनसंख्या में जापान की हिस्सेदारी केवल 1.9% है, जबकि भारत की 19%। भारत में रह रहे बुजुर्गों की कई प्रकार की जरूरतों के लिए देखभाल की जा रही है। इसमें स्वतंत्र जीवन, सहायता प्राप्त जीवन, डिमेंशिया पीड़ित बुजुर्गों के लिए मेमोरी केयर सुविधाएं शामिल हैं, जहां उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत होती है। बुजुर्गों को इन सभी जगहों पर विभिन्न स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं और लाइफस्टाइल सपोर्ट दिया जा रहा है। यहां तक कि 2025 की शुरुआत में तो 'बेबी बूमर्स' यानी 1948 से 1964 के बीच जन्मे लोग भी वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में शामिल आ गए हैं और मौजूदा सेवानिवृत्त समुदाय का हिस्सा हैं। इस वर्ग के बहुत कम ही लोग बचे हैं, जो पारिवारिक ढांचे में बदलाव के कारण सहायता प्राप्त जीवन की तलाश करते हुए अब भी काम कर रहे हैं।

बुजुर्गों की देखभाल के परंपरागत मॉडल को दृढ़ता के साथ पीछे छोड़ते हुए ये नए जमाने का समुदाय सामाजिक जुड़ाव-व्यक्तिगत स्वायत्तता पर अधिक जोर देता है। सेविल्स इंडिया के एमडी-रिसर्च एंड कंसल्टिंग, अरविंद नंदन कहते हैं, ये केवल जनसांख्यिकीय प्रतिक्रिया नहीं, आधारभूत ढांचे की अनिवार्यता है। दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिक उन टियर-2 शहरों की तलाश में हैं, जहां चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं ठीक-ठाक हैं, लेकिन प्रदूषण कम है और आसपास खूब हरियाली है। यही कारण है कि रियल्टर्स ऐसे शहरों पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे ऊपर बताए गए हैं। और जो धीरे-धीरे इस बदलाव का वास्तविक जरिया बन रहे हैं। फंडा यह है कि उम्रदराज हो रहे भारत की सुरक्षा के लिए योजना बनाना और इस तरह अपने बुजुर्गों की चिंता करना ना केवल मानवता का ही एक रूप है, बल्कि यह युवा आबादी के लिए भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

भारत दबंग और गतिशील अर्थव्यवस्थाः राजनाथ सिंह

ट्रंप के टैरिफ वॉर पर रक्षामंत्री का करारा जवाब

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे 'दबंग और गतिशील' अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि 'सबके बॉस तो हम हैं' का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है. राजनाथ सिंह ने ट्रंप पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि कुछ "बॉस" भारत की तेज विकास दर से जलते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "कुछ लोग भारत की तेज प्रगति से खुश नहीं हैं. उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है. 'सबके बॉस तो हम हैं', तो भारत इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है?"

भारत की अर्थव्यवस्था रोकने की कोशिश

अमेरिका ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क और अतिरिक्त 25% पेनल्टी लगाई है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रख रहा है. यह कदम वॉशिंगटन द्वारा इस आरोप के बाद उठाया गया कि भारत, रूस के युद्ध प्रयासों को वित्तपोषित कर रहा है. इसके साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की अर्थव्यवस्था को "डेड" बताया और आगे शुल्क बढ़ाने की धमकी भी दी थी. राजनाथ सिंह ने कहा, "कुछ देश चाहते हैं कि भारत में बने उत्पाद, भारतीय हाथों से तैयार चीजें, बाकी देशों की तुलना में महंगी हो जाएं, ताकि दाम बढ़ने पर दुनिया उन्हें खरीदना बंद कर दे." उन्होंने भरोसा जताया कि अब दुनिया की कोई ताकत भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने से नहीं रोक सकती.

रक्षा निर्यात में मजबूती

रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र को भारत की मजबूती का उदाहरण बताते हुए कहा, "हम 24,000 करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहे हैं. यह नए भारत का नया रक्षा क्षेत्र है और निर्यात लगातार बढ़ रहा है." उन्होंने स्पष्ट किया कि टैरिफ विवाद का इस क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ा है.

टैरिफ को लेकर भड़के अमेरिका के पूर्व NSA

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद से ही ट्रंप की हर तरफ आलोचना हो रही है। अब अमेरिका में भी ट्रंप के फैसले को लेकर आवाज उठने लगी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति ने भारत और अमेरिका के दशकों पुराने रणनीतिक प्रयासों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ खासकर रूसी तेल खरीदने पर जो टैरिफ लगाया गया है, उस वजह से भारत रूस और चीन के करीब जा सकता है।

भारत को निर्यात बढ़ाने और आयात घटाना होगाः गडकरी

अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान किया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव आ गया है। इस बीच टैरिफ के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज की दुनिया में जो देश दादागिरी कर रहे हैं, वे ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनके पास तकनीक है। विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत के निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर हमारे निर्यात और अर्थव्यवस्था की दर बढ़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। जो लोग दादागिरी कर रहे हैं, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनके पास तकनीक है। अगर हमें बेहतर तकनीक और संसाधन मिल जाए, तो हम किसी पर धौंस नहीं जमाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि विश्व कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान कहा कि हम वैश्विक स्तर पर विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इन सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी ज्ञान है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से की बात

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूक्रेन में जारी संघर्ष पर चर्चा की और द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की. आईबी के आधिकारिक बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से संबंधित ताजा घटनाक्रमों की जानकारी दी. इसके बाद पीएम मोदी ने पुतिन को उनके विस्तार से किए गए आकलन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और रूस-यूक्रेन के संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में भारत के स्थायी रुख को फिर से दोहराया. वहीं, बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-रूस के संबंधों और द्विपक्षीय एजेंडे में हुई प्रगति की भी समीक्षा की और दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने को लेकर प्रतिबद्धता को दोहराया है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस साल के अंत में होने वाले भारत-रूस के वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया है. रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा पूरी होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को एक नई गति देने की उम्मीद है।

'वोट चोरी' पर चुनाव आयोग से भिड़ेंगे राहुल गांधी

नई दिल्ली। फर्जी मतदाता मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगाते हुए कहा कि वो नियमों के अनुसार स्पष्ट घोषणा और शपथ पत्र प्रस्तुत करें या फिर अपने झूठे और भ्रामक आरोपों के लिए देश से सार्वजनिक माफी मांगें. वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष ने अब इसके खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया है. ऐसा लग रहा है कि मानो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से दो-दो हाथ करने की ठान ली है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार (10 अगस्त, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वोट चोरी 'एक व्यक्ति, एक वोट' के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है. वोट चोरी 'एक व्यक्ति, एक वोट' के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है।

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ़ है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें. उन्होंने आगे कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़ कर इस मांग का समर्थन करें - http://votechori.in/ecdemand पर जाएं या 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें. ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है

आर्मेनिया-अजरबैजान की 37 साल पुरानी जंग खत्म

नई दिल्ली। आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं ने ट्रम्प की मौजूदगी में शुक्रवार को व्हाइट हाउस में शांति समझौते पर साइन किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 37 साल पुरानी जंग को खत्म कराने के लिए समझौता करा दिया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल ने शुक्रवार को ट्रम्प की मौजूदगी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों में विवादित इलाके के लिए एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी है। इस कॉरिडोर को ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम दिया जाएगा। यह कॉरिडोर अजरबैजान को उसके नखचिवान एंक्लेव इलाके से जोड़ेगा, जो आर्मेनिया से होकर गुजरेगा। दोनों नेताओं ने ट्रम्प और उनकी टीम को इसका श्रेय दिया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। इस दौरान ट्रम्प ने एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का दावा किया।

युद्ध में नैरेटिव मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिकाः उपेंद्र द्विवेदी

नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि किसी भी युद्ध में नैरेटिव मैनेजमेंट की बड़ी भूमिका होती है. उन्होंने कहा कि अगर किसी पाकिस्तानी से पूछो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी जीत हुई या हार हुई तो वो बोलेंगे कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बना है तो पाकिस्तान की जीत ही हुई होगी.

आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने इस नैरेटिव से अपने नागरिकों को यह विश्वास दिलाया है कि भारत के साथ हालिया संघर्ष में उनकी जीत हुई है. जनरल द्विवेदी ने IIT मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि इसी तरह आप घरेलू आबादी, विरोधी की आबादी और तटस्थ आबादी को प्रभावित करते हैं. सेना प्रमुख (COAS) ने कहा, "नैरेटिव मैनेजमेंट प्रणाली एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें बड़े पैमाने पर एहसास होता है क्योंकि जीत मन में होती है. यह हमेशा मन में ही रहती है. अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि आप हारे या जीते तो वह कहेगा मेरे प्रमुख फील्ड मार्शल बन गए हैं, हम ही जीते होंगे, इसीलिए वह फील्ड मार्शल बने हैं."उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की रणनीति का अपने तरीके से मुकाबला किया. सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करके जनता तक अपना संदेश पहुंचाया. उन्होंने कहा, "रणनीतिक संदेश बहुत ज़रूरी था और इसीलिए हमने जो पहला संदेश दिया, वह था न्याय हुआ. मुझे बताया गया है कि आज दुनिया में हमें जितने हिट मिले, उनमें से सबसे ज़्यादा हिट इसी से मिले।"

बिहार में वोटर लिस्ट फॉर्मेट में नहीं होगा बदलावः चुनाव आयोग

नई दिल्ली। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के वोटर लिस्ट फॉर्मेट में बदलाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक कर इसे गलत और भ्रामक बताया है. चुनाव आयोग ने कहा कि 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट रोल जिस फॉर्मेट में अपलोड किया गया था और यह अब भी उसी फॉर्मेट में उपलब्ध है. चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि 1 अगस्त 2025 को जारी ड्राफ्ट रोल जिस फॉर्मेट में था और यह फॉर्मेट अभी भी उपलब्ध है. मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का फॉर्मेट बदलाव नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पर फैल रही यह जानकारी पूरी तरह तथ्यहीन है. गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के फॉर्मेट को बदलकर कई अहम जानकारियां हटाई हैं, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठता है।

देश में एशियाई शेर पांच साल में 32 प्रतिशत बढ़े

नई दिल्ली। गुजरात के अमरेली में अभी सबसे एशियाई शेर हैं, जिनमें करीब 82 व्यस्क नर और 117 व्यस्क मादा शेर और 79 शावक शामिल हैं। मितियाला वाइल्डलाइफ सेंचुरी में शेरों की संख्या में सबसे ज्यादा तेजी आई है, उसके बाद भावनगर मेनलैंड औऱ दक्षिणी पूर्वी तट शामिल हैं। भारत में एशियाई शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने रविवार को विश्व शेर दिवस पर 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते पांच वर्षों में देश में एशियाई शेरों की संख्या में 32 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसके बाद देश में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है।

जनसंख्या हुई 891

रिपोर्ट के अनुसार, बारदा वाइल्डलाइफ सेंचुरी, जेतपुर और आसपास के इलाकों में, बाबरा जसदान और आसपास के इलाकों समेत कुल नौ स्थानों पर एशियाई शेरों की संख्या 497 पाई गई है। वहीं पहली बार कॉरिडोर इलाके में 22 एशियाई शेर पाए गए हैं। सैटेलाइट की मदद से यह गिनती की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 'भारत को एशियाई शेरों का घर होने में बेहद गर्व है। बीते कुछ वर्षों में देश में शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है। साल 2015 में जहां 523 शेर थे, वहीं 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 891 हो गई है। हमें इस मामले में जबरदस्त सफलता मिली है। वर्ल्ड लायन डे पर हम अपने शेरों को बचाने का प्रण लेते हैं।'

अमरेली में सबसे ज्यादा शेर

बीते एक दशक में देश में शेरों की संख्या 70 प्रतिशत बढ़ी है। गुजरात के अमरेली में अभी सबसे एशियाई शेर हैं, जिनमें करीब 82 व्यस्क नर और 117 स्क मादा शेर और 79 शावक शामिल हैं। मितियाला वाइल्डलाइफ सेंचुरी में शेरों की संख्या में सबसे ज्यादा तेजी आई है, उसके बाद भावनगर मेनलैंड औऱ दक्षिणी पूर्वी तट शामिल हैं। हालांकि कुछ इलाकों में शेरों की संख्या में कमी भी आई है, जिनमें गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भावनगर तट के इलाके शामिल हैं।

इसी साल वनडे से भी संन्यास लेंगे रोहित और कोहली?

2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए चयनकर्ता की रणनीति में फिट नहीं

नई दिल्ली। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली ODI से भी संन्यास लेने जा रहे हैं? ये सवाल ताजा रिपोर्ट आने के बाद उठने लगा है. दोनों दिग्गज तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तानी कर चुके हैं, वह अब सिर्फ ODI फॉर्मेट में खेलते हैं. टेस्ट के बाद अब वनडे टीम की बागडोर भी युवा खिलाड़ियों के हाथों में जाती दिख रही है और रोहित-कोहली का 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलने का सपना टूट सकता है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद एकसाथ इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. इंग्लैंड दौरे से पहले रोहित-कोहली ने एक हफ्ते के अंतराल में टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले ली थी. भारत का अगला टूर्नामेंट एशिया कप है, जो सितंबर में टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत का अगला वनडे ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो अक्टूबर में होगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये सीरीज इन दोनों की आखिरी वनडे सीरीज भी साबित हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अगर रोहित और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भी खेलना है तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना पड़ सकता है. ये ट्रॉफी दिसंबर के अंत में शुरू होगी. बता दें कि दोनों इस साल शुरुआत में रणजी ट्रॉफी के बचे हुए मैचों में खेले थे, क्योंकि टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने फैसला किया था कि बिना कोई ठोस कारण के अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल रहे प्लेयर्स डोमेस्टिक टूर्नामेंट को मिस नहीं कर सकते. इसमें भी रोहित और कोहली का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, जिसके बाद दोनों ने टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले लिया था.

रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया कि इन दोनों दिग्गजों ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है लेकिन अब युवा खिलाड़ियों की लाइन लंबी है और चयनकर्ता और टीम प्रबंधन 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे हैं. इस रिपोर्ट में टीम प्रबंधन के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि रोहित और कोहली आगामी वनडे वर्ल्ड कप टीम के लिए हमारी रणनीति में फिट नहीं होंगे.

एशिया कप तक फिट नहीं हुए सूर्या तो कौन करेगा कप्तानी?

नई जिल्ली। सूर्यकुमार यादव की कुछ समय पहले सर्जरी हुई थी. उनके एशिया कप में खेलने पर सस्पेंस बरकार है. अगर वो फिट नहीं हुए तो ये 2 खिलाड़ी टीम इंडिया की कप्तानी करने के लिए मजबूत दावेदार हैं. क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर के बीच यूएई में होगा. भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है. इसके बाद 14 तारीख को भारत बनाम पाकिस्तान मैच होगा, ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भारत 19 को ओमान के खिलाफ खेलेगी. टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की कुछ समय पहले सर्जरी हुई थी, वह अपनी फिटनेस हासिल करने मेहनत कर रहे हैं. लेकिन अगर वह टूर्नामेंट तक पूरी तरह फिट नहीं हुए तो भारतीय टीम की कमान कौन संभालेगा?

शुभमन गिल: इंग्लैंड दौरे पर पहली बार टेस्ट की कमान संभालते हुए शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन किया, सभी की वाहवाही लूटी. उन्होंने बल्ले से भी कई रिकॉर्ड बनाए, इसके बाद माना जा रहा है कि वह एशिया कप स्क्वॉड में शामिल होंगे. सूर्या जब कप्तान बने थे तब गिल को उपकप्तान बनाया गया था, ऐसे में अगर सूर्या नहीं खेले तो एशिया कप में भारत की कप्तानी शुभमन गिल संभाल सकते हैं.

बतौर कप्तान शुभमन गिल का T20 करियर

कुल मैच: 5
भारत ने जीते: 4
भारत ने हारे: 1

हार्दिक पांड्या: ऑलराउंडर प्लेयर हार्दिक भारत के लिए बल्ले और गेंद, दोनों से महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं. उन्होंने गुजरात टाइटंस को अपनी कप्तानी में टीम के पहले ही सीजन में चैंपियन बनाया था।

बतौर कप्तान हार्दक का T20 करियर

कुल मैच: 16
भाररत ने जीते: 10
भारत ने हारे: 5
टाई: 1

रेप केस में फंसे क्रिकेटर यश दयाल पर लगा बैन

नई दिल्ली। भारत के उभरते हुए तेज गेंदबाज यश दयाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. रेप केस में फंसे यश दयाल पर अब बैन लग गया है. आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलने वाले लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज यश दयाल इस साल यूपीटी20 लीग में खेलते नहीं दिखेंगे. UPCA ने यश दयाल पर बैन लगा दिया है. यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने यह फैसला जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में यश दयाल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होने के बाद लिया है, जिसमें उनपर पर 17 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था. यश दयाल को आखिरी बार मई की शुरुआत में आईपीएल 2025 ट्रॉफी जीतने वाली आरसीबी टीम का हिस्सा रहते हुए देखा गया था. इसके बाद से वह क्रिकेट के मैदान से दूर हैं. गोरखपुर लायंस द्वारा 7 लाख में खरीदे गए यश दयाल को यूपीसीए ने यूपीटी20 2025 में भाग लेने से प्रतिबंधित किया।

ट्रंप के 50% टैरिफ की मार से बिगड़ सकता है 'मेक इन इंडिया' प्लान

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं. यह भारत के आत्मनिर्भर मिशन के सामने एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उभर सकता है. अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि सस्ते रूसी तेल की लगातार खरीदारी के चलते भारत पर जो अतिरिक्त पेनल्टी ट्रंप ने लगाई है, उसका सीधा असर देश की मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धा पर पड़ेगा.

गौरतलब है कि भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिका की ओर से 31 जुलाई को की गई थी, जो 7 अगस्त से प्रभावी हो चुकी है. इसके अलावा, 6 अगस्त को अतिरिक्त जुर्माने के तौर पर 25 प्रतिशत पेनल्टी का ट्रंप ने ऐलान किया, जो 28 अगस्त से लागू होगी. हालांकि, दोनों देशों के बीच संभावित बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं.

मूडीज ने शुक्रवार को कहा कि अन्य एशियाई देशों की तुलना में उच्च टैरिफ दरों के कारण भारत के महत्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' अभियान पर असर पड़ सकता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को झटका लग सकता है. विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा.अगर रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ प्रभावी होते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता को कम करना है, उस पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है.

कोच गंभीर ने मुझ पर दिखाया पूरा भरोसाः संजू

नई दिल्ली। संजू सैमसन ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें लगातार मौके नहीं मिले. वह टीम से अंदर बाहर होते रहे, कभी 1 तो कभी 2 मैच के बाद उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा. उन्होंने अश्विन के साथ इंटरव्यू में इस पर बात करते हुए बताया कि कैसे गौतम गंभीर ने उनके करियर को बचाया. उनकी सूर्यकुमार यादव के साथ क्या बातचीत हुई और जब वह गंभीर की कोचिंग में भी फ्लॉप हुए तो कोच ने उनसे क्या कहा और कैसे आत्मविश्वास दिलाया. गौतम गंभीर की कोचिंग में संजू सैमसन को ओपनिंग करने का मौका मिला, उन्होंने काफी प्रभावित भी किया. इसी को लेकर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर सैमसन से सवाल किया तो विकेट कीपर बल्लेबाज ने जवाब दिया, "मैं अपने करियर में टीम से अंदर बाहर होता रहा, 8-9 सालों में सिर्फ 15 मैचों के करीब ही खेल पाया था. मैं कभी टीम में होता, कभी बाहर लेकिन मैने हमेशा खुद को पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ाया. वर्ल्ड कप के बाद अचानक बदलाव हुआ. गौतम गंभीर ने कोच का पद संभाला, सूर्यकुमार यादव कप्तान बने." सैमसन ने बताया कि सूर्यकुमार यादव ने दलीप ट्रॉफी के दौरान सूर्यकुमार यादव ने मुझे से कहा कि तुम्हारे लिए बड़ा मौका है, अगले 7 मैचों में तुम्हे लगातार मौके मिलेंगे.

30 सितंबर के बाद ATM से नहीं निकलेंगे 500 रुपये के नोट

नई दिल्ली। कई मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया था कि एटीएम से 500 रुपये के नोट निकलना बंद हो जाएगा. इस पर वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है. सरकार की ओर से संसद में कहा गया कि जनता की लेन-देन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या संतुलित रूप से उपलब्ध रहे. छोटे मूल्य के नोटों तक लोगों की आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि वे: 30 सितंबर 2025 तक 100 और 200 रुपये के नोटों की संख्या 75 प्रतिशत तक सुनिश्चित करें, और 31 मार्च 2026 तक इनकी संख्या को 90 प्रतिशत तक बढ़ाएं।

ICICI के सेविंग्स अकाउंट में अब रखना होगा 50 हजार रुपए मिनिमम बैलेंस

नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है. बैंक ने अपने मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस (MAMB) को लेकर नया नियम जारी किया है. बैंक ने 1 अगस्त, 2025 या उसके बाद खोले जाने वाले सेविंग्स अकाउंट के लिए मौजूदा MAMB को 10,000 रुपये से बढ़कर सीधे 50,000 रुपये कर दिया है. यह नियम सिर्फ मेट्रो सिटीज और शहरों के लिए लागू है. यानी कि यहां रहने वाले बैंक के ग्राहकों को अपने बचत खाते में एक महीने के दौरान न्यूनतम 50,000 रुपये का औसत बैलेंस रखना होगा. जबकि पहले सिर्फ 10,000 रुपये रखने की जरूरत पड़ती थी. कुल मिलाकर बैंक ने अपने MAMB में 5 गुना की बढ़ोतरी की है.

वहीं, सेमी-अर्बन शाखाओं में ग्राहकों को अब एक महीने के दौरान 5,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये का न्यूनतम औसत बैलेंस रखना होगा. वहीं, ग्रामीण शाखाओं में न्यूनतम औसत बैलेंस को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है. यानी कि सिर्फ दो गुना ही वृद्धि की गई है. बैंक के ये अपडेटेड टर्म्स और कंडीशन प्रभावी तिथि से केवल नए खोले गए बचत खातों पर ही लागू होंगे, ICICI बैंक के जो ग्राहक 1 अगस्त से अपने अकाउंट में संशोधित न्यूनतम राशि बनाए रखने में विफल रहेंगे, उन्हें अपडेटेड शुल्क अनुसूची के अनुसार पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा, बैंक ने नकद लेनदेन के शुल्क में भी बदलाव किया है.

ग्राहकों को अब शाखाओं और कैश रिसाइक्लर मशीनों पर प्रति माह तीन निःशुल्क नकद जमा लेनदेन की सुविधा मिलेगी. इसके बाद हर अतिरिक्त लेनदेन पर 150 रुपये का शुल्क लगेगा. हर महीने आप एक बार में 1 लाख रुपये तक डिपॉजिट कर सकेंगे. इसके बाद प्रति 1,000 रुपये पर 3.5 परसेंट या 150 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा. थर्ड पार्टी कैश डिपॉजिट लिमिट 25,000 रुपये तक तय कर दी गई है.

संकट में घिरे सुप्रीम कोर्ट से अनिल को राहत

नई दिल्ली। लोन फ्रॉड मामले का सामना कर रहे कारोबारी अनिल अंबानी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दो सहायक कंपनियों BSES यमुना पावर लिमिटेड और BSES राजधानी पावर लिमिटेड को 28,483 करोड़ रुपये का बिजली बकाया वसूलने की इजाजत दे दी है. रिलायंस इंफ्रा ने कहा कि बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी पावर पर 31 जुलाई, 2025 तक कुल 28,483 करोड़ रुपये बकाया है. रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडियरी कंपनियां 1 अप्रैल, 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से शुरू होने वाले 4 वर्षों की अवधि में 28,483 करोड़ रुपये की नियामक परिसंपत्तियों की वसूली करेंगी. बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी पावर में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की 51 परसेंट हिस्सेदारी है, जबकि शेष 49 परसेंट हिस्सेदारी दिल्ली सरकार के पास है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर समेत 34 शहरों में खुलेंगी सेंट्रल लाइब्रेरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पूरे प्रदेश में अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन (नालंदा परिसर) के निर्माण का विस्तार किया है। अब तक 34 नए नालंदा परिसरों के लिए कुल 237 करोड़ 57 लाख 95 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं।

ये लाइब्रेरी सिर्फ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायगढ़ जैसे बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर, पेंड्रा जैसे दूरस्थ वनांचलों में भी बन रही हैं। इन लाइब्रेरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन अध्ययन की सुविधा, शांत वातावरण और उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर वर्ग के युवाओं को, चाहे वे शहर में हों या दूरस्थ इलाके में, समान अवसर मिल सके।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 17 नगरीय निकायों में 18 नालंदा परिसरों के लिए 125 करोड़ 88 लाख रुपये स्वीकृत हुए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 परिसरों के लिए 111 करोड़ 70 लाख रुपये मंजूर किए गए, जिनमें से 11 परिसरों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं।

500 और 250 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण

10 नगरीय निकायों में 500 सीटर लाइब्रेरी बनाई जाएंगी – दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, भिलाई नगर निगम, जशपुर, लोरमी, गरियाबंद और रायपुर।

22 शहरों में 250 सीटर लाइब्रेरी बनेंगी – धमतरी, चिरमिरी, कवर्धा, जांजगीर-नैला, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कांकेर, नारायणपुर, बलरामपुर, मुंगेली, खैरागढ़, सक्ती, पेंड्रा, सारंगढ़, सूरजपुर, बैकुंठपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कुनकुरी, बसना और अंबागढ़-चौकी।

रायगढ़ में बनेगी सबसे बड़ी लाइब्रेरी

रायगढ़ में 700 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण सीएसआर फंड से किया जा रहा है। इसके लिए रायगढ़ नगर निगम और एनटीपीसी के बीच 42 करोड़ 56 लाख रुपये का करार हुआ है।

रायपुर में दो और लाइब्रेरी बनेंगी

राजधानी रायपुर में फिलहाल 1000 सीटर नालंदा परिसर-सह-ऑक्सी रीडिंग जोन, 800 सीटर तक्षशिला सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-स्मार्ट रीडिंग जोन, 500 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी, संचालित हैं। यहां से पिछले 5 वर्षों में 400 युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाई है। जल्द ही रायपुर में एक 1000 सीटर (22.80 करोड़) और एक 500 सीटर (11.28 करोड़) नई लाइब्रेरी का निर्माण प्रारंभ होगा।

गंदगी फैलाने वालों पर रायपुर नगर निगम की सख्त कार्रवाई

रायपुर। राजधानी में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। जुलाई के आखिरी सप्ताह से शुरू हुए विशेष अभियान के तहत अब तक 1,861 लोगों को ई-चालान भेजा गया है, जिन पर कुल 22.23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें 327 लोगों ने अब तक राशि का भुगतान नहीं किया है। निगम का कहना है कि यह कार्रवाई प्रदेश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर की जा रही है।

निगम के अनुसार सड़क पर कचरा फेंकना, खुले में शौच करना, ग्रीन नेट लगाए बिना निर्माण कार्य करना, मलबा और रेत-गिट्टी सड़क पर छोड़ना, गीला-सूखा कचरा अलग न करना, समारोह के बाद गंदगी छोड़ना, स्ट्रीट वेंडरों द्वारा कचरा फैलाना, और अस्पतालों द्वारा मेडिकल वेस्ट का गलत निपटान जैसी गतिविधियां इस कार्रवाई के दायरे में हैं। उल्लंघन करने वालों की पहचान उनके भवन या परिसर पर लगी प्रॉपर्टी आईडी प्लेट से की जा रही है। इस व्यवस्था के लिए नगर निगम ने विशेष मोबाइल एप और ई-चालान पोर्टल विकसित किया है। निगम कर्मचारी मौके पर फोटो खींचकर एप में अपलोड करते हैं, जहां फोटो के आधार पर स्वतः नियम उल्लंघन और जुर्माने की राशि तय हो जाती है। पहले यह काम मैनुअल रसीद से होता था, जिसमें हेरफेर की गुंजाइश रहती थी। अब सिस्टम पूरी तरह डिजिटल है। जुर्माना नहीं भरने वालों की राशि उनके संपत्ति कर में जोड़ी जाएगी और टैक्स का भुगतान करते समय यह भी वसूला जाएगा। वहीं, यदि किसी अन्य व्यक्ति, मवेशी या वाहन द्वारा किसी के घर के सामने कचरा डाला जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति 24 घंटे के भीतर आपत्ति दर्ज कराकर ई-चालान निरस्त करा सकता है।

कांग्रेस के निष्क्रिय पदाधिकारियों पर एक्शन

रायपुर शहर जिला युवा कांग्रेस कमेटी और विधानसभा इकाई भंग

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज रायपुर शहर जिला इकाई पर बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए पूरी कमेटी और विधानसभा इकाई को भंग कर दिया है। यह कार्रवाई निष्क्रियता के आधार पर की गई है। प्रदेश महासचिव एवं जिला प्रभारी आदिल आलम खैरानी और शहर जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप ने रविवार को आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लागू कर दिया। युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष तुषार गुहा ने बताया कि लंबे समय से संगठन के कार्यक्रमों में पदाधिकारियों और विधानसभा इकाई की सक्रिय भागीदारी नहीं हो रही थी। लगातार निष्क्रिय रहने और पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखने के कारण कमेटी को भंग करना पड़ा है।

संगठन ने साफ कहा है कि आने वाले समय में संगठन में केवल सक्रिय, कर्मठ और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। गुहा ने बताया कि हमारा लक्ष्य युवा कांग्रेस की ताकत और प्रभाव को और अधिक मजबूत बनाना है।

इसलिए हुआ ये एक्शन

रायपुर शहर जिला युवा कांग्रेस कमेटी में पिछले कुछ महीनों से कई कार्यक्रमों में पदाधिकारियों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई थी। पार्टी की आंतरिक बैठकों में भी इस मुद्दे पर असंतोष जताया जा रहा था। अब संगठन ने कड़ा कदम उठाकर साफ संकेत दे दिया है कि निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जल्द ही नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

पुलिस के सामने मसीही समाज के लोगों से मारपीट

रायपुर में धर्मांतरण पर बवाल, 3 हिरासत में

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्मांतरण-मतांतरण को लेकर फिर बवाल हुआ है। रविवार की सुबह सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के कुकुर बेड़ा में हिंदू संगठनों ने एक मकान का घेराव कर दिया। हिंदू संगठन ने मसीही समाज के लोगों पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके से एक महिला समेत 3 संदेहियों को हिरासत में लिया।

वहीं सरस्वती नगर थाना परिसर में हिंदू संगठन और मोहल्लेवासियों ने हिरासत में लिए गए युवकों को पीट दिया। पुलिस ने पीड़ित युवकों को भीड़ से छुड़ाया और आरोपियों पर FIR करने की बात कही है। इस मामले में हिंदू संगठन का कहना है कि उन्होंने मारपीट नहीं की। युवक भाग रहे थे, इसलिए मोहल्लेवासियों ने पीट दिया। हिंदू संगठन का कहना है कि इष्ट देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी। पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। रायपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना की सूचना मिली तो 3 थानों की फोर्स को मौके पर रवाना किया।

रविवार की सुबह कुकुर बेड़ा में मोहल्लेवासियों ने हिंदू संगठनों को बुलाया। उनका कहना था कि, मोहल्ले के एक मकान में पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे। मकान में 30 से 35 लोग मौजूद थे। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सरस्वती नगर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मकान से एक महिला और 2 युवकों को हिरासत में लिया। उन्हें पूछताछ के लिए लेकर थाने लेकर आई। हिंदू संगठन का कहना है कि युवक भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मोहल्लेवासियों ने उन्हें पीट दिया।

रायपुर में अवैध प्लाटिंग पर निगम की कार्रवाई, FIR दर्ज

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर, जोन 7 के जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में नगर निवेश विभाग ने रामनगर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के दो अलग-अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई की है। इसके तहत गुढ़ियारी थाना में संबंधित प्लाटिंगकर्ताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई। नगर निगम जोन 7 नगर निवेश विभाग के मुताबिक, बिना कॉलोनी विकास अनुज्ञा और बिना अनुमति लिए अवैध रूप से प्लाट काटकर बेचने की शिकायत पर अतिरिक्त तहसीलदार और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पहले मामले में भूमि स्वामी/प्लाटिंगकर्ता — संतोषी बाई, शिव कुमार, महेंद्र साहू, शिव बाई और भावा बाई — के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दूसरे मामले में, रामनगर क्षेत्र में नरेन्द्र, जयप्रकाश, अजय, रमा, ललिता, अनिता, सविता, महेश कुमार, रवि प्रकाश, भीमा, रामदुलारे और ईश्वर कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने भूखंड को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर अवैध रूप से बेच दिया। दोनों मामलों में, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) के तहत अवैधानिक और दंडनीय अपराध करने पर, नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए गुढ़ियारी थाना, ग्राम चिरहुलडीह (रामनगर क्षेत्र) में एफआईआर दर्ज की गई है।

रायपुर नगर निगम ने 42 प्रस्तावों को दी मंजूरी

महिलाओं, युवाओं और शहर विकास पर खास जोर

रायपुर। नगर निगम की महापौर परिषद (एमआईसी) की गुरुवार को हुई बैठक में राजधानी के विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े 42 प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं, शहर के बुनियादी ढांचे के विस्तार और धार्मिक स्थलों के कायाकल्प जैसे निर्णय शामिल हैं।

महिलाओं के लिए शांति गृह और वर्किंग हॉस्टल

शांति गृह: 5 करोड़ रुपये की लागत से नरैया तालाब के पास खाली हुई स्वीपर कॉलोनी की जगह बनेगा। यहां घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना की शिकार महिलाएं रह सकेंगी।

वर्किंग हॉस्टल: भैसथान, नरैया तालाब के पास और पंडरी बस स्टैंड के पीछे तीन हॉस्टल का निर्माण।

रोजगार: गारमेंट फैक्ट्री का संचालन निजी कंपनी को देने का प्रस्ताव, 500 स्थानीय महिलाओं को रोजगार देने की शर्त के साथ।

पर्यावरण और पौधारोपण

- वुमेन फॉर ट्री अभियान और पौधों की जियो टैगिंग योजना को मंजूरी।
- 7 स्थानों पर पौधरोपण, देखरेख और सिंचाई का जिम्मा स्वसहायता समूहों को।
- अमृत मित्र योजना के तहत 2 करोड़ 48 लाख 65 हजार रुपये की स्वीकृति।

शहरी सेवाएं और बुनियादी ढांचा

- महापौर, सभापति और एमआईसी सदस्यों के लिए वाहन और चालक स्वीकृत।
- 87 चालक, 2 डिप्लोमा धारक इंजीनियर, 2 मैकेनिक, 1 वेल्डर, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर और 1 हेल्पर की नियुक्ति।
- 19 नई सड़कों (66.19 किमी) पर मशीनीकृत सड़क सफाई का विस्तार, लागत 51 करोड़ 88 लाख रुपये।

अन्य स्वीकृत प्रस्ताव

- निराश्रित पेंशन योजना: 428 नए प्रकरण स्वीकृत।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना: 88 नए प्रकरण स्वीकृत।
- 3 अधिकारियों की संविदा अवधि एक वर्ष बढ़ाने की अनुशंसा।
- 9 कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय का भुगतान।
- जोन-9 और रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में सीसी रोड निर्माण।
- दलदल सिवनी में 9 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से दिव्यांग इनक्लूजिव पार्क।

सुकमा में गृहमंत्री शर्मा बोले नक्सल खात्मे के लिए सभी की भूमिका अहम

समीक्षक बैठक में अंदरूनी इलाकों में निर्माण कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश

शहर सत्ता/रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की सुदृढ़ रणनीति और सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई के चलते नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और इसके खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। उक्त बातें उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा अपने सुकमा प्रवास के दौरान समीक्षा बैठक में कही।

सुकमा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस अहम समीक्षा बैठक में व्यापारी संगठन, सड़क और खदान निर्माण से जुड़े संघटन, सर्व आदिवासी समाज, जनजाति सुरक्षा मंच, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मोबाइल और मेडिकल दुकान संचालक, वनवासी कल्याण समिति तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिले के विकास, सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सुकमा की जनता अब विकास की राह पर आगे बढ़ रही है और गुमराह करने वाले तत्वों का प्रभाव खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंदरूनी इलाकों में विकास कार्यों में जनसहभागिता बढ़ रही है, वह इस बात का संकेत है कि जल्द ही शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास की गति और तेज होगी तथा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण कार्यों को अधिक संसाधनों के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन क्षेत्रों में कार्य करने वालों को सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस विभाग निभाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय युवाओं को इन निर्माण कार्यों में प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने, रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ पर सख्ती से नियंत्रण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सुकमा जिले में लघु वनोपज की अपार संभावनाएं हैं और इनके प्रसंस्करण से स्थानीय लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने स्व सहायता समूहों की आय बढ़ाने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार करने और निर्माण कार्यों के टेंडर में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में मॉडल बनकर उभर रहा है बस्तर संभाग

रायपुर। बस्तर संभाग में नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन क्षेत्र के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्त विस्तार की दिशा में लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के सतत मार्गदर्शन में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं आज तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं।

बस्तर के छ :जिला चिकित्सालयों, दो सिविल अस्पतालों और 41 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल प्रणाली का सफल संचालन किया जा रहा है, जिससे ओपीडी पंजीकरण, परामर्श, जांच, दवा वितरण तथा मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां अब एक डिजिटल मंच पर उपलब्ध हो रही हैं। इसके तहत मरीजों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं मिल रही हैं। डिजिटल तकनीक के इस समावेशन ने अस्पतालों में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और मरीजों की संतुष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अस्पतालों का हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन (HFR) और चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ का हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन (HPR) सुनिश्चित किया गया है। अस्पताल परिसरों में आभा कियोस्क स्थापित कर मरीजों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) बनाने की सुविधा दी जा रही है। स्कैन एंड शेयर एवं आभा आईडी के माध्यम से ऑनलाइन ओपीडी पंजीयन की सुविधा से मरीजों को लम्बी कतारों से राहत मिली है और उन्हें त्वरित सेवाएं मिल रही हैं। डिजिटल नवाचारों का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से सामने आया है। जिला चिकित्सालय बस्तर में मई, जून और जुलाई 2025 के दौरान कुल 60,045 ओपीडी पंजीयन दर्ज किए गए, जिनमें से 32,379 पंजीयन आभा लिंक के माध्यम से हुए।

अब हाथियों से बचाने हाथी मितान एवं हाथी वार्ता केन्द्र

शहर सत्ता/रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा हाथी-मानव द्वंद को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। धरमजयगढ़ वनमंडल के ओंगना गांव में हाथी मितान और हाथी वार्ता केंद्र की शुरुआत की गई है। वन मंत्री श्री कश्यप ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हाथी प्रभावित अन्य गांवों में भी जल्द ही यह योजना लागू की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को समय पर सतर्क कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह पहल वन विभाग और ग्रामीणों के बीच समन्वय बनाकर हाथियों से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करेगी। इस योजना के तहत गांव के एक जागरूक व्यक्ति को हाथी मितान के रूप में चुना गया है। यह मितान गांव में हाथियों के विचरण और उनकी की उपस्थिति, उनके व्यवहार और सुरक्षा के तरीकों की जानकारी समय पर ग्रामीणों को देंगे। साथ ही, गांव में हाथी वार्ता केंद्र स्थापित किया गया है, जहां ग्रामीणों को हाथियों से जुड़ी जानकारी और सुरक्षा के उपाय बताए जाएंगे। इसी तरह हाथी वार्ता केंद्र में गांव का नक्शा बनाकर जंगल के नजदीक स्थित घरों को चिन्हांकित किया गया है। इन घरों के निवासियों का मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड में रखा गया है, ताकि हाथियों की उपस्थिति की सूचना उन्हें तुरंत दी जा सके और समय रहते वे सुरक्षित स्थान पर जा सकें। इस अभियान में वन विभाग के अधिकारी, नोवा नेचर वेलफेयर सोसायटी, हाथी मित्र दल और स्थानीय लोग सक्रिय रूप से शामिल हुए।

पाम की खेती से बढ़ रही किसानों की आमदनी

- **खाद्य तेल उत्पादन को मिल रहा बल**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक धान की खेती के साथ अब पाम (तेल पाम) की खेती किसानों के लिए नई आय का स्रोत बन रही है। राज्य सरकार, केंद्र के सहयोग से, पाम ऑयल उत्पादन और बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। राज्य में राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन के तहत पिछले चार वर्षों में 2,689 हेक्टेयर भूमि पर पाम की खेती की जा चुकी है। पाम ऑयल का उपयोग खाद्य पदार्थों जैसे बिस्कुट, चॉकलेट, इंस्टेंट नूडल्स और स्नैक्स के अलावा साबुन, क्रीम, डिटर्जेंट और जैव ईंधन के निर्माण में भी होता है। पाम की खेती बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, बेमेतरा, जशपुर, सरगुजा, कोरबा और बिलासपुर में प्रोत्साहित की जा रही है। साल 2021 से 2024 के बीच 1,150 किसानों ने 1,600 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पाम की खेती शुरू की है। रायगढ़ के चक्रधरपुर गांव के किसान राजेंद्र मेहर ने बताया, "मेरी जमीन सालों से खाली पड़ी थी। तकनीकी मार्गदर्शन और पाम की खेती के लाभ जानने के बाद इसे अपनाया। अब अच्छी अतिरिक्त आमदनी हो रही है।"

कृषि विभाग के अनुसार, महासमुंद जिले में 611 हेक्टेयर में पाम की खेती हो रही है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। सरकारी योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 29,000 रुपये मूल्य के 143 पौधे मुफ्त दिए जाते हैं। पाम की खेती में रोपण, बाड़बंदी, सिंचाई, रखरखाव और अंतर-फसल की कुल लागत लगभग 4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर आती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। शेष राशि किसान बैंक ऋण से जुटा सकते हैं। इसके अलावा, कृषि रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, जल संचयन, वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों, पाम कटर, तार जाल, मोटर चालित उपकरण, चारा कटर और ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे उपकरणों पर भी अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है।

मंत्री रामविचार नेताम ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री से की मुलाकात

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मंत्री श्री नेताम ने इस मौके पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री सिंह को ऑपरेशन "सिंदूर" की सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री सिंह से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे नक्सल अभियान के संबंध में भी चर्चा की। मंत्री नेताम ने राज्य सरकार द्वारा नियद नेल्लानार अभियान के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातियों के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

मलेशिया सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों की दो दिवसीय नेचर हीलिंग कैंप में रही उत्साही भागीदारी

वैश्विक स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बना जीपीएम

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को पर्यटन के नजरिए से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को स्थानीय प्रशासन और पर्यटन समितियों की मेहनत से पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान लगातार बढ़ रही है। बनमनई इको फाउंडेशन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय नेचर हीलिंग कैंप में मलेशिया सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। मलेशिया से चार विदेशी मेहमान इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इनके साथ ही बिहार से फिल्म निर्माता आर्यन चंद्रप्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार विभाष झा, डॉ अरविंद गुप्ता बंगलौर, ए के सिंह (सेवानिवृत्त प्रबंधक, कोल इंडिया), इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय और अमलाई के शोधार्थी सहित 20 अन्य प्रतिभागी कैंप में शामिल हुए।

कार्यक्रम में पर्यावरणविद् संजय पयासी ने जिले के दो प्रमुख जलप्रपात लक्ष्मणधारा और झोझा जल प्राप्त की ट्रैकिंग कराई। मलेशियाई मेहमानों का पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन पहुंचे पर आत्मीय स्वागत किया गया। स्थानीय लोग उत्साह से भर उठे। सभी ने उनके साथ फोटो खिंचवाई। स्थानीय लोगों के इस उत्साह से विदेशी अतिथि अत्यंत प्रसन्न और प्रभावित हुए। उन्हें पेंड्रा की हरी सब्जियां, चरवाहों की बाँस की टोपी, और लक्ष्मणधारा की ऑफ-रोड राइडिंग ने उन्हें एक अनोखा अनुभव दिया। लक्ष्मणधारा पर्यटन समिति द्वारा परोसे गए पकौड़े और लेमन जिंजर चाय का उन्होंने भरपूर आनंद लिया। इतने सुदूर क्षेत्र में भी पर्यटन समिति के उत्कृष्ट प्रबंधन ने सभी पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर दिया। अरपा नदी पर स्थित लक्ष्मणधारा जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर था। पानी की उड़ती बूंदों में छनकर आती सूर्य किरणें सुंदर इंद्रधनुष रच रही थीं। यही पर्यटन का आकर्षण है, जहां अलग-अलग भाषा, देश, परिवेश और संस्कृति के लोग अपने-अपने रंग लिए मिलते हैं। शाम को पर्यटक लमना होमस्टे पहुंचे, जहां ग्रामीण महिलाओं ने तिलक लगाकर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया।

गांव वालों का प्रेम और सम्मान "अतिथि देवो भव" की परंपरा को सजीव कर रहा था। रात्रि में प्रस्तुत गौरा-गौरी का स्थानीय लोकनृत्य सभी को थिरकने पर मजबूर कर गया। लोक नृत्य और गायन, जो ग्रामीणों के पारंपरिक मनोरंजन के साधन हैं, ने अपनी अभिव्यक्ति से ऐसा अद्भुत दृश्य रचा जो स्थानीय सीमा से निकलकर वैश्विक हो गया। यही सांस्कृतिक आदान-प्रदान लमना गांव के सामुदायिक पर्यटन का आदर्श मॉडल है, जो न केवल आर्थिक रूप से ग्रामीणों को सशक्त कर रहा है, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टि से भी उन्हें समृद्ध बना रहा है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

बीजेपी के घर-घर तिरंगा को कांग्रेस ने बताया पाखंड

52 सालों तक संघ में नहीं फहराए तिरंगा

शहर सत्ता/रायपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा अभियान को राजनीति के पाखंड करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि तिरंगा हर भारतीय के लिए आन बान शान है, लेकिन भाजपाइयों के लिए यह केवल राजनैतिक विषयवस्तु है। भाजपा का राष्ट्रवाद और तिरंगा प्रेम केवल दिखावा है, असलियत में तिरंगा के प्रति भाजपाइयों के मन में हिकारत है भाजपा तो मुखौटा है उनके पित्र संगठन के लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का बार-बार अपमान किया तीन रंग को अपशगुन बताएं, अब केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए घर घर यात्रा निकाल रहे हैं। भाजपा के तय कार्यक्रम के अनुसार

भाजपाई आत्म अवलोकन करें कि उनके पूर्वजों ने क्यों तिरंगे को अपमानित किया

तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर को जोड़े जाने को मोदी सरकार की नाकामी पर परदेदारी करार देते हुए कहा कि सेना के शौर्य पर राजनीति करना भाजपा का चरित्र बन चुका है। पुलवामा और गलवान पर भाजपाई मौन हो जाते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 32 बार यह दावा किया है कि उन्होंने व्यापार का लालच देकर अपने सिंदूर स्थगित करवाया, मोदी, शाह सहित तमाम भाजपाई इस पर मौन क्यों है? पहलगाम हमले के साढ़े तीन महीने बाद भी आज तक आतंकी ना पकड़े गए ना ही उन्हें मारा गया किसके संरक्षण में वे भागे, सुरक्षा में गंभीर चूक के लिए जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की गई? भाजपा बताये आजादी के बाद 52 सालों तक संघ के मुख्यालय नागपुर में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया था? आजादी के बाद दशको तक भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस ने क्यों राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं किया था?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा भाजपाई आत्म अवलोकन करें कि उनके पूर्वजों ने क्यों तिरंगे को अपमानित किया था। आज भी संघ के शाखाओं में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता? देशवासी तो गर्व से अपने घरों में तिरंगा फहराते है, संघ की शाखाओं में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने ही 1929 में लाहौर अधिवेशन के समय रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, उसके बाद से हर साल 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाने लगा। आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर देश भक्ति का जलसा निकालने की नौटंकी करने वालों के पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों के पैरोकार की भूमिका में खड़े थे।

तिरंगा अभियान....BJP का हर नेता देगा 50 झंडे

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को चार्ज करेगी। बीजेपी पदाधिकारियों ने रविवार 10 अगस्त को बैठक लेकर इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने बैठक लेकर इस संबंध में निर्देश जारी किया है। बीजेपी नेता नवीन मार्कंडेय ने बताया कि 'मोर तिरंगा मोर अभिमान' अभियान सफल रहे, इसलिए सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और विधायक, मंडल सदस्यों समेत पदाधिकारियों को शक्ति केंद्र में 50 तिरंगा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी नेताओं के अनुसार संगठन के पदाधिकारियों की कार्यशाला पूरी हो चुकी है। बीजेपी के शक्ति केंद्रों से तिरंगा हर घर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि, संगठन ने 12 लाख तिरंगों का ऑर्डर दिया है। ये तिरंगे छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आएंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी की है। वहीं तिरंगा यात्रा की प्रभारी नीलू शर्मा ने बताया कि, 10 से 14 अगस्त तक मंडलों में तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा की इसमें प्रमुख भूमिका रहेगी। वहीं 13 से 15 अगस्त तक घरों, संस्थानों और कार्यालयों में कार्यकर्ता तिरंगा फहराएंगे। बीजेपी ने 50 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल 24 लाख घरों तक तिरंगा पहुंचाया गया था। इस बार का लक्ष्य दोगुना है, इसलिए जिला, मंडल और बूथ स्तर तक बैठकें की जा रही हैं। बीजेपी नेताओं ने प्रदेशवासियों से अपील की है, कि वो इस अभियान में शामिल हो और अपने घर के बच्चों से झंडारोहण कराए।

चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करना ठीक नहीं: सीएम साय

कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आते हैं तो सब ठीक रहता है

शहर सत्ता/रायपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस पर पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करना ठीक नहीं है। सीएम साय ने आगे कहा कि जब उनके (कांग्रेस) पक्ष में नतीजे आते हैं तब सब ठीक रहता है, लेकिन जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और आयोग पर सवाल उठाते हैं।

दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दो दिवसीय जशपुर दौरे के बाद रविवार शाम रायपुर लौटे। इस दौरान रायपुर पुलिस ग्राउंड में उन्होंने ये बातें कहीं। वहीं, सीएम साय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने दौरे की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जशपुर में महतारी वंदन की बहनों के साथ रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया और महिला स्व सहायता समूह की 12 महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ई-रिक्शा वितरित किए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि तीन विकासखंडों में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का शुभारंभ भी किया गया है।

पीसीसी चीफ बोले; चुनाव आयोग का आचरण ही बड़ी मिस्ट्री

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गंभीर चिंताजनक

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश की चुनावी प्रणाली विशेष कर मतदाता सूची की गड़बड़ियों के जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है वह गंभीर है तथा देश के चुनाव प्रणाली में निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। देश के लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाये गये सवालों की गहन जांच हो और पूरे प्रकरण में जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा के लोकसभा चुनाव के मतदाता सूची की गड़बड़ियों के पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किया है। एक प्रधानमंत्री आवास में 80 वोटर, 46 वोटर एक बियर क्लब के पते पर 68 वोटर होना एक ही मतदाता का बार-बार नाम आना और सभी के द्वारा अलग-अलग मतदान करने के साक्ष्य बताते है कि देश के चुनावों में धांधली हो रही है और वोटरों की चोरी हो रही है। चुनाव आयोग, नेता प्रतिपक्ष के साक्ष्यों से मुंह नहीं चुरा सकता। यह देश के प्रजातंत्र का सवाल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में रही है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद वोटों की चोरी का संदेह यकीन में बदल गया। महाराष्ट्र में 5 साल के मुकाबले सिर्फ 5 माह में ज्यादा वोटर्स जोड़े गये वहां पर मतदाताओं की संख्या राज्य की वयस्क आबादी से भी ज्यादा है। यही नहीं महाराष्ट्र के चुनावों में शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अचानक जबर्दस्त उछाल आ गया था। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अनेकों बार उठाया, चुनाव आयोग को चार चिट्ठियां भी लिखी, चुनाव आयोग ने गोलमटोल जवाब दिया।

कांग्रेस का आरोप, राखड़ माफियाओं के कब्जे में विभाग

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में राखड़ माफियाओ को सरकारी संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोटे कमीशन के लालच में पर्यावरण विभाग के नियमों से बाहर जाकर अवैध गतिविधियों को संरक्षण दे रही है सरकार। ग्राम पंचायत को बिना विश्वास में लिए, बिना ग्रामसभा के प्रस्ताव के पावर प्लांट और राखड़ बांधों से जहां कहीं भी राखड़ डंप किए जा रहे है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक समस्या कोरबा और रायगढ़ जिले में है जो पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी का गृह जिला भी है। कोरबा जिले में तो बालको, दर्री, जमनीपाली में रोड के किनारे जो छोटे-छोटे पोखर, डबरी, तालाब थे वे पूरी तरह से राख से भर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में राखड़ निपटान की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक हितों को प्राथमिकता देते हुए, बालको, अडानी पॉवर, मारुति पॉवर, एसीबी पॉवर जैसी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्राकृतिक जल स्रोतों को 'लो लाइन' के नाम पर पाटकर राखड़ भरने की अनुमति दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ के नौ राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन निर्वाचन आयोग ने किया रद्द

शहर सत्ता/रायपुर। राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन करवाकर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले दलों पर अब निर्वाचन आयोग एक्शन ले रहा है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के 9 और देश के 334 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने यह कदम जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत उठाया गया है। आयोग के इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की संख्या कम हो गई है। आपको बता दे, कि प्रदेश में अब तक राजनीतिक दलों की संख्या 55 है। चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद इनकी संख्या 46 हो गई है।

इन दलों पर चुनाव आयोग का एक्शन

- छत्तीसगढ़ एकता पार्टी
- छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
- छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी
- छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी
- छत्तीसगढ़ विकास पार्टी
- पृथक बस्तर राज्य पार्टी
- राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी
- राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी
- राष्ट्रीय समाजवाद पार्टी संविधान मोर्चा

- **आदिवासी बहुजन, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी समेत 9 राजनैतिक दलों के नेताओं ने नहीं लड़ा चुनाव**

यह है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951

भारत निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों में इस निएम के तहत एक्शन लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक परिदृश्य को अधिक पारदर्शी बनाने और सक्रिय दलों को ही मान्यता देने के उद्देश्य से की गई है। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के अनुसार दलो का राजिस्ट्रेशन निर्वाचन आयोग में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम में शर्त रहती है, कि राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी नहीं उतारते और छह साल तक वो इसी परंपरा को बरकार रखते है, तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है।

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ का उभरता पर्यटन हब, जहां आस्था, संस्कृति और प्रकृति का संगम

छत्तीसगढ़ का दक्षिणी जिला दंतेवाड़ा अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के लिए देशभर के पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे विकास कार्यों और सुरक्षा इंतजामों के चलते अब यह इलाका पूरी तरह से सुरक्षित और सुगम हो चुका है, जिससे यहां का पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है।

धार्मिक आस्था का केंद्र

दंतेवाड़ा का मुख्य आकर्षण माँ दंतेश्वरी मंदिर है, जो देश के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, यहां देवी सती का दांत गिरा था। बारसूर में स्थित दंतेश्वरी देवी गुड़ी, बत्तीसा मंदिर, मामा-भांजा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, नागफनी मंदिर और सोलह खंबा मंदिर जैसे प्राचीन धार्मिक स्थल क्षेत्र की ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय विरासत को दर्शाते हैं। बारसूर को 'मंदिरों और तालाबों का नगर' कहा जाता है, जहां कभी 147 मंदिर और 147 तालाब हुआ करते थे।

प्राकृतिक पर्यटन स्थल

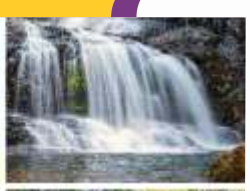

सातधार जलप्रपात – इंद्रावती नदी की सात धाराओं से बना, अपनी निर्मल जलधारा और पथरीले भूभाग के लिए प्रसिद्ध।

फुलपाड़ जलप्रपात – अरनपुर घाटी में स्थित, जहां दूधिया सफेद पानी की धाराएं चट्टानों पर गिरती हैं।

झारालावा जलप्रपात – 60 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह जलप्रपात बैलाडीला पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है।

मलांगीर और स्तापिगिरी जलप्रपात – घने जंगलों में बसे, शांत और रोमांचक अनुभव देने वाले स्थल।

जनजातीय संस्कृति और उत्सव

फागुन मड़ई – 45 दिनों तक चलने वाला दक्षिण छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला, जिसमें पारंपरिक लोकनाट्य और शिकार खेल विशेष आकर्षण हैं।

घोटपाल मेला – स्थानीय देवता उसुड़ी ताड़ो देव को समर्पित।

समलूर मेला – महाशिवरात्रि पर नंदिराज पहाड़ी की तलहटी में आयोजित।

यहां की दंडामी माड़िया जनजाति, जिसे बायसन-हॉर्न माड़िया भी कहा जाता है, अपने विशिष्ट मुकुट और बायसन की चाल को दर्शाने वाले नृत्य के लिए प्रसिद्ध है।

पर्यावरण और साहसिक पर्यटन

मातातरई झील – कयाकिंग और बोटिंग के लिए प्रसिद्ध, जहां शांत वातावरण में पर्यटक प्रकृति का आनंद लेते हैं।

बूढ़ा तालाब – नौकायन सुविधा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ इको-टूरिज्म का केंद्र।

कुआहाररास बांध – पिकनिक और प्रकृति दर्शन के लिए आदर्श स्थल।

गनमन तराई – ऐतिहासिक मंदिर अवशेषों के साथ शांत जलाशय।

सुविधाएं और कनेक्टिविटी

पर्यटकों की सुविधा के लिए दंतेवाड़ा में मुचनार शुभ्र होमस्टे, मुचनार रिवर कैंप और तुले आया ट्राइबल होमस्टे जैसे आवास विकल्प मौजूद हैं। छिन्दनार नदी पुल (712 मीटर लंबा) अबूझमाड़ के 40 से अधिक गांवों को जोड़ता है और वर्षभर संपर्क बनाए रखता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संदेश में दंतेवाड़ा को न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी उपयुक्त बताते हुए पर्यटकों से यहां आने का आग्रह किया है। स्थानीय प्रशासन इको-टूरिज्म, होमस्टे, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ट्रेकिंग रूट को बढ़ावा देकर क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने के प्रयास में है।

नेता, अफसर और कैदियों की भी कलाई में सजी राखी

रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह और विश्वास का प्रतीक : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह ग्राम बगिया स्थित कैंप कार्यालय में रक्षाबंधन के अवसर पर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित बहनों ने राखी बांधकर आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना की हितग्राही दीदियों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाएँ, मितानिन और स्व-सहायता समूह की बहनों ने भी मुख्यमंत्री श्री साय की कलाई पर राखी बांधी और उनके दीर्घायु की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व भाई-बहन के अटूट रिश्ते, स्नेह और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और मोदी जी की गारंटी का अर्थ है—वादा पूरा होने की गारंटी। मुख्यमंत्री श्री साय ने जशपुर के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जशपुर जिले में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी एवं उद्यानिकी कॉलेज, 200 बिस्तरों का अस्पताल और बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए हर्राडांड (कुनकुरी) में प्रदेश का पाँचवाँ पावर प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जशपुर के विकास में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर श्री उपेंद्र यादव, श्री सुनील गुप्ता, सरगुजा कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गा, आईजी श्री दीपक कुमार झा, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार, जनप्रतिनिधिगण, स्व-सहायता समूह की दीदियाँ और हितग्राही महिलाएँ बड़ी संख्या में उपस्थित थीं।

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुकमा में एक भावनात्मक और ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। नक्सल पुनर्वास केंद्र सुकमा में आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों और बस्तर फाइटर के दीदियों ने उपमुख्यमंत्री को राखी बांधकर भाईचारे, विश्वास और शांति का सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि विगत माह जब मैं सुकमा आया था तो मैंने पुनर्वास केंद्र की बहनों से वादा किया था कि रक्षाबंधन का पर्व आपके साथ मनाऊँगा। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मेरा यह वादा पूरा हुआ। आप सभी को मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक आपका भाई है आपको चिंता करने या डरने की कोई बात नहीं है।

अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कलाई में कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने रक्षासूत्र बांधकर, माथे में तिलक लगाकर और श्रीफल देकर अपनी भावनाएं प्रकट की। पूर्व सीएम श्री बघेल ने भी अपनी सियासी बहनों की रक्षा और प्रदेश की माताओं की सुरक्षा के लिए कामना की।

केन्द्रीय जेल रायपुर में कैदियों ने मनाया रक्षाबंधन

रायपुर। केन्द्रीय जेल रायपुर में रक्षाबंधन के पावन पर्व भावनाओं और आत्मीयता से परिपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर बंदियों को उनकी बहिनों और परिजनों से मिलने का अवसर प्रदान किया गया। बहिनों ने अपने बंदी भाईयों की पारंपरिक तरीके पूजा अर्चना कर उनके कलाई पर रक्षासूत्र बांधा और उनके स्वस्थ, सुखी एवं उज्जवल भविष्य की मंगलकामनाएं कर भाई-बहिन के रिश्ते को और मजबूत बनाया। जेल अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहिन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। परिवार से मिलने का अवसर कैदियों के मनोबल को बढ़ाता है और समाज में पुनः स्थापित होने की उनकी इच्छा का सशक्त करता है। जेल में करीब 1281 बंदियों से मिलने 2953 बहिने आई तथा कुल 42 महिला बंदियों से 75 भाई मिलने आये। साथ ही जेल में ही परिरूद्ध 16 महिला बंदियों ने अपने बंदी भाईयों को राखी बांधी। जेल की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। पूरे कार्यक्रम में अनुशासन, सौहार्द और भावनात्मक अपनत्व का अद्भूत संगम देखने को मिला।

जिन भाइयों की बहनें नहीं आ पाईं या जिनकी बहनें नहीं हैं। उनके लिए भी विशेष कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान ब्रम्हाकुमारी और गायत्री परिवार की बहनें और सेंट्रल जेल रायपुर पहुंचीं और कैदियों को राखी बांधी।

राखी के साथ पहनाया हेलमेट

रायपुर। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक अनोखी मिसाल पेश की गई। गुण्डरदेही विकासखंड के ग्राम परसवानी में अपने भाई विनोद यादव के घर पहुंची दो बहनें ममता यादव और माधुरी यादव ने इस बार राखी के साथ भाई की सुरक्षा का भी संकल्प लिया। जिला प्रशासन बालोद द्वारा हाल ही में शुरू किए गए हेलमेट जागरूकता अभियान से प्रेरित होकर दोनों बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधने के साथ उनके सिर पर हेलमेट भी सजाया। उन्होंने इसे भाई की रक्षा के लिए रक्षाबंधन पर दिया गया एक विशेष उपहार बताया।

बहनों का कहना था कि आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट न पहनने से गंभीर चोटें और जान जाने के मामले सामने आते हैं। जब हम अपने भाई की दीर्घायु की कामना करते हैं, तो

दो बहनों ने भाई को दिया सुरक्षा का अनोखा तोहफ़ा

उसकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाने चाहिए। विनोद यादव ने बताया कि कुछ समय पहले वे एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे, उस समय हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर और आंख पर गंभीर चोट आई थी। उन्होंने कहा कि अब मुझे एहसास है कि हेलमेट जान बचा सकता है। मेरी बहनों ने मुझे यह अनमोल तोहफ़ा देकर न सिर्फ मेरी सुरक्षा का ध्यान रखा है बल्कि मुझे हमेशा हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित भी किया है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे जिला प्रशासन के हेलमेट जागरूकता अभियान का पालन करें और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन न चलाएं।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)।